twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शुक्रवार, 18 अप्रैल, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 162, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वक्फ कानून पर हुई सुप्रीम सुनवाई, अंतरिम आदेश जारी

वक्फ संशोधन कानून के विवादित प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होंगे

नई दिल्ली

वक्फ कानून पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई के दौरान गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वक्फ संशोधन कानून के विवादित प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होंगे। यानी फिलहाल इस कानून पर यथास्थिति बनी रहेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने केंद्र सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं हैं। मेहता ने कहा कि आप एक ऐसा कानून रोकने जा रहे हैं, जिसे संसद ने पास किया है।

मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मेहता ने कहा कि मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ धाराओं को देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कई गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। ऐसे में आम लोगों के हितों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 1995 के कानून के तहत वक्फ में रजिस्टर्ड संपत्तियों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब मेहता ने जवाब दिया कि यह बात खुद कानून में शामिल हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति न की जाए।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह से बदल जाए, हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं।

'जब हम अदालत में बैठते हैं, तो अपना धर्म भूल जाते हैं'

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के पहले दिन ही बहस लंबी चली। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच वक्फ एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब हम अदालत में बैठते हैं, तो अपना धर्म भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में गैर-न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

कोर्ट ने नियुक्तियां रोकीं, केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब

कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को सात दिनों के भीतर इस पर जवाब देने को कहा है, केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी। इससे पहले 16 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि 'वक्फ बाय यूजर' की व्यवस्था को हटाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगा सकता है।

चीफ जस्टिस ने कहा था कि संसद से पारित कानून पर बिना विस्तार की सुनवाई के कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को देखते हुए कोर्ट ऐसा कर सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए।

वक्फ से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने किया स्वागत

नई दिल्ली

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि वैचारिक हमला है।

केंद्र सरकार जिसे सुधार बता रही है, दरअसल वह अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के चेयरमैन एवं सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहां आज पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सिंघवी ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 26 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपने धर्म का अभ्यास, निर्वहन और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है। वह धर्म से जुड़ी संस्थाओं का संचालन व प्रबंधन कर सकता है और उनके चुनावों में नामित हो सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पांच खंडपीठों के पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक वर्ग की संस्थाओं की स्वायत्तता को इस हद तक कम करना कि वह समाप्त हो जाए, असंवैधानिक है।

उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 11 में चुनावित श्रेणी को हटाकर शत-प्रतिशत नामांकन का प्रावधान स्वायत्तता के सिद्धांत के विरुद्ध है। वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधान 9 और 14 पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रावधान 9 कहता है कि केंद्रीय वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 12 लोग गैर मुस्लिम हो सकते हैं।

मैं खुद जाकर मुर्शिदाबाद की हकीकत देखूंगा: राज्यपाल

कोलकाता

वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, 'मैं खुद मैदान में जाकर वहां की हकीकत देखूंगा। मैं मामले को निष्पक्ष तरीके से देखूंगा। स्थिति पर काबू पा लिया गया है। हमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कदम उठाने चाहिए। मैं निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद का दौरा करूंगा'।

मंदी से प्रभावित होगा आईटी सेक्टर- एचडीएफसी एमडी

नई दिल्ली

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध रोज एक नया रूप ले रहा है। इससे दुनियाभर के प्रमुख शेयर बाजारों में जबरदस्त दहशत का माहौल है। भारत के शेयर बाजार पर भी इसका असर है। इस साल अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रही देश की प्रमुख शेयर ब्रोकिंग कंपनी एचडीएफसी सिक्युरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रेली का कहना है कि वैश्विक अनिश्चतता का सबसे कम असर भारत पर होगा। आईटी, फार्मा व कुछ निर्यात संबंधी उद्योग सेक्टरों के अलावा अन्य सेक्टर की कंपनियों की स्थिति बेहतर रहेगी। वह यहां तक मानते हैं कि वर्ष 2025-26 में निवेशकों को बेहतरीन शेयरों में निवेश का बढ़िया मौका मिलेगा। हालांकि वह निवेशकों को यह भी सलाह देते हैं कि उन्हें सही तरीके से शोध करके बाजार में प्रवेश करना चाहिए। हमारे पास एक स्थिर सरकार है, जीडीपी की वृद्धि दर लगातार अच्छी बनी हुई है, प्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि भी उत्साहजनक है। भारत की जनसंख्या अभी जिस स्तर पर है, उसका भी पूरा लाभ मिलेगा। हमारे पास विकास की ऊंचाई छूने के लिए लंबी रेनवे है। यह भी याद रखिए कि भारत की इकोनमी अमूमन घरेलू मांग पर निर्भर है यानी वैश्विक स्तर पर जो उथल-पुथल अभी हम देख रहे हैं, उसका भारत पर कम असर होगा।

दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार

नई दिल्ली

देश के ज्यादातर राज्यों में दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 3-4 डिग्री ज्यादा है।

'कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं'

नई दिल्ली

आतंकवादियों को पोषित और संरक्षित करने वाली पाकिस्तान की आर्मी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं, मुनीर ने कश्मीर राग भी अलापा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दावा किया है कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है।

कश्मीर को लेकर पाक सेना के बयान का भारत ने दिया जवाब

मुनीर की इस टिप्पणी पर भारत ने

करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर को गले की नस बताने वाली टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "कोई विदेशी चीज किसी के गले की नस में कैसे फंस सकती है? यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पाकिस्तान के साथ एकमात्र संबंध उस देश द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों को खाली करना है।"

हम हर एंगल में हिंदुओं से अलग हैं: आसिम मुनीर

पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कार्यक्रम में आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम हर एंगल में हिंदुओं से अलग है, हमारा रिवाज, हमारा धर्म, हमारी सोच सब इनसे अलग है। हम दो राष्ट्र हैं, एक नहीं। हमने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए है, हमें पता है कि इस देश को बनाने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है। मुनीर ने भारत का नाम न लेते हुए कहा,"क्या पाकिस्तान के दुश्मन ये सोचते हैं कि सिर्फ 1500 आतंकवादी देश की किस्मत बदल देंगे, हम जल्द ही आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे।

दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, वक्फ कानून के लिए धन्यवाद दिया

नई दिल्ली

दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम के लिए उन्हें धन्यवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि यह संशोधन समुदाय की लंबे समय से मांग थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण पर भरोसा जताया। केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया

प्लेटफार्म एक्स पर मुलाकात का वीडियो साझा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दाऊदी बोहरा समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया, जो उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन पर उनका भरोसा बहुत ही प्रेरक था।

जस्टिस वर्मा नकदी मामले में अब तक दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी, उपराष्ट्रपति ने उठाए सवाल

नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी बरामदगी मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक संज्ञेय अपराध में कानून के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और संविधान केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही ऐसे मामलों में छूट प्रदान करता है। धनखड़ ने कहा कि एक महीना बीत जाने के बाद भी हमें नहीं पता की मामले में जांच कहां तक पहुंची है। धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा इंटर्न के छठे बैच को संबोधित करते हुए कहा कि मामले को प्रकाश में आए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक इसमें कोई जांच प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। घटना के सात दिन बाद मामला मीडिया में आने के बाद ही प्रकाश में आया था। कानून के शासन के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में उसकी आपराधिक न्याय प्रणाली की शुद्धता उसकी दिशा निर्धारित करती है। आपराधिक मामलों में सबसे पहले एफआईआर दर्ज किया जाना जरूरी है। यह नियम स्वयं उन पर और बाकी सभी पर लागू होता है। एक संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज न करना भी एक अपराध है, लेकिन हम सबके मन में एक प्रश्न है कि अभी तक फिर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित न्याय तंत्र से अनुमति लेनी जरूरी कर दिया गया है।

राष्ट्रपति को निर्देश देना असंवैधानिक: उपराष्ट्रपति धनखड़

नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर विचार के लिए तीन महीने का समय तय किया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का अधिकार है लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहां राष्ट्रपति को निर्देशित किया जा सके और वह भी

किस आधार पर। धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा इंटर्न के छठे बैच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा होता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपालों द्वारा ली जाती है। वहीं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश ये सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। उन्होंन कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति रखता है।

शरीयत नहीं, संविधान से चाहिए न्याय

याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम शख्स;केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस विवादास्पद मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई कि क्या मुसलमानों को अपने धर्म को त्यागे बिना उनकी पैतृक संपत्तियों से जुड़े मामलों का निपटान शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने केरल के त्रिशूर जिले के निवासी नौशाद केके द्वारा दायर याचिका पर गौर किया। इसमें उन्होंने कहा था कि वह अपना धर्म इस्लाम को छोड़े बिना शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत अपनी संपत्ति से जुड़े मामलों का निपटान चाहते हैं।

मुर्शिदाबाद-बांग्लादेश पर विपक्ष के मौन ने इन्हें चौराहे पर नंगा किया: योगी

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अपनी सरकार में हुए राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और माफिया मुक्त शासन की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और माफियावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योजनाओं में घोटाले कर लंदन में होटल बनाए, वही लोग प्रदेश को लूटने और जातियों में बांटने के लिए जिम्मेदार

हैं। मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, माफियावाद और परिवारवाद से अपना साम्राज्य खड़ा किया, वही लोग अब मुर्शिदाबाद जैसे मामलों पर मौन हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है।

जो हाल आज मुर्शिदाबाद का है वो कभी यूपी के शहरों का होता था

सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है। पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, ठेके लेते थे, दंगे करवाते थे और महिलाओं व व्यापारियों को परेशान करते थे। लोग त्योहारों पर सशंकित रहते थे। अब यूपी में त्योहार शांतिपूर्ण और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो हाल आज मुर्शिदाबाद का है वही कभी यूपी में मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहर के हुआ करते थे। मुख्यमंत्री ने पूर्वी यूपी में इंसेफलाइटिस जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई, इनमें से ज्यादातर बच्चे अल्पसंख्यक समाज के होते थे, लेकिन किसी नेता के आंसू नहीं बहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी इंसेफलाइटिस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे वोट बैंक नहीं होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वन डिस्ट्रक्ट वन माफिया होते थे, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज हैं और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं।

योजनाओं के पैसे लूटकर बनाए लंदन में होटल

सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए बताया कि 2016 में बिना किसी तैयारी के इसका शिलान्यास कर दिया गया। तब 15,200 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट अनियमितताओं से भरा था।

सौ देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा भारत : राजनाथ सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली । देश में बनाए गए रक्षा उपकरण करीब 100 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए यह बात कही। राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा पांच सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें कुल 509 रक्षा उपकरण, हथियार प्रणाली और रक्षा प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इनका उत्पादन अब देश में ही किया जाएगा।

नई दिल्ली में रक्षा तैयारी से जुड़े विषय पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2013-14 में देश का रक्षा निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए का था। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। करीब सौ देशों को भारत में बने रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। इस साल रक्षा निर्यात बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए और साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है।उन्होंने बताया कि डिफेंस पीएसयू ने भी पांच सूचियां जारी की हैं। इनमें कुल 5,012 उत्पाद शामिल हैं। इनका भी उत्पादन अब अनिवार्य रूप से भारत में ही किया जाएगा। हम बेहद मजबूती के साथ, नियोजित तरीके से आत्मनिर्भर और मजबूत डिफेंस सेक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़

रहे हैं। 'मेक इन इंडिया' की ओर आगे बढ़ते समय घरेलू कंपनियों के हितों का भी ध्यान रखा गया। इसी कारण सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए रक्षा बजट का 75 प्रतिशत, घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया हुआ है। यह देश की घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों का ही परिणाम है कि 2014 के आसपास जहां हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, वहीं आज यह लगभग एक लाख 27 हजार करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। इस साल हमारा लक्ष्य है कि रक्षा उत्पादन 1.60 लाख करोड़ रुपए और 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपए को पार कर जाए।

राजनाथ सिंह ने कहा कि जब 2014 में एनडीए सत्ता में आया था तो सबसे बड़ी चुनौती रक्षा क्षेत्र को लेकर एक अजीब सोच की थी, जो इस क्षेत्र के बारे में दीर्घावधि योजना और विजन के अभाव से पैदा हुई थी। उस समय फोर्स फॉर द फ्यूचर की बात सोचने का भी साहस लोग नहीं करते थे क्योंकि फोर्स फॉर द प्रेजेंट के लिए भी कोई तैयारी दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने बताया कि देश में एक मजबूत रक्षा क्षेत्र तैयार करने के लिए मजबूती से काम नहीं हो रहा था। रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस समय की सरकार की बस यही सोच थी कि बहुत होगा तो आयात कर लेंगे। सबसे पहले इस सोच को बदला गया, यह निर्णय लिया गया कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करेगा। देश में एक ऐसा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। यह कॉम्प्लेक्स केवल भारत की जरूरतों को नहीं, बल्कि दुनिया में रक्षा निर्यात की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा।

दिग्विजय के बाबरी मस्जिद को 'शहीद' बताने वाले पुराने बयान पर सियासी तकरार

एजेंसी

भोपाल । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा बाबरी मस्जिद को 'शहीद' बताने वाले एक पुराने बयान पर सियासी तकरार हो रही है। भाजपा ने जहां दंगे-फसाद के पीछे कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया है, वहीं दिग्विजय सिंह ने वीडियो के कुछ हिस्सों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। इसमें सिंह ने बाबरी मस्जिद को ढहाने पर उसे 'शहीद' कहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि दंगा-फसाद के पीछे कांग्रेस है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दिग्विजय सिंह के एक वीडियो से यह बात प्रमाणित होती है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करने के साथ मंत्री सारंग ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का कबूलनामा सामने आ गया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि बाबरी मस्जिद ÷शहीद÷ हुई और उसके बाद उन्होंने ही दंगे-फसाद करवाए। आज यह वीडियो वायरल हुआ है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जो हम पहले से कहते हैं कि हर दंगा-फसाद के पीछे कांग्रेस है, अब दिग्विजय सिंह ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दंगे करवाए थे। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता।

राहुल गांधी के गुजरात-बिहार की धरती पर पांव रखते ही भाजपा ने ईडी को मैदान में उतारा : अलका लांबा

पटना । अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने ईडी के नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर करने पर भाजपा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात और बिहार की धरती पर पांव रखते ही भाजपा ने ईडी को मैदान में उतार दिया है। दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा बौखला गई है। 1937 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए अखबार बनाए थे, आज उस अखबार के बने 85 साल हो गए हैं। देश को आजाद होने के 75 साल हो गए हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसे बने 10 साल हो गए हैं। मामला 13 साल से चल रहा है, सरकार आपकी, ईडी आपकी, सत्ता आपकी, फिर भी क्यों कुछ नहीं साबित कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके सारे आरोप झूठे हैं। ईडी मतलब 'इलेक्शन डिपार्टमेंट' हो गई है।' कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी बुलाया था, क्या मिला? इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। केवल मुद्दों से भटकाने के लिए यह सब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की बैसाखी के दम पर दिल्ली की सरकार चल रही है। बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी। यहां सरकार गिरते ही, केंद्र की भाजपा सरकार गिरने वाली है।

मायावती ने सपा पर लगाया दलित वोटों के लिए तनाव और हिंसा भड़काने का आरोप

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर दलित वोटों के लिए तनाव और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा की बयानबाजी और कार्यक्रमों को संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करार दिया। मायावती ने दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों से सपा के बहकावे में न आने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, यह इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहां किसी भी हद तक जा सकती है। मायावती ने कहा, अतः दलितों के साथ-साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही, ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका-टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। इससे पहले बुधवार को मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की थी। इस बैठक में दोनों राज्यों में पार्टी संगठन की समीक्षा की गई थी।

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया सात दिन का समय, डिनोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रहेगी रोक

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए।

एजेंसी

नई दिल्ली । वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी

देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप 'वक्फ बाय यूजर' को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया। अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।

पहले यूपी के शहर भी मुर्शिदाबाद की तरह दंगों की आग में जलते थे : सीएम योगी

● बांग्लादेश की घटनाओं पर विपक्ष चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है।

एजेंस

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और माफियावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने योजनाओं में घोटाले कर लंदन में होटल बनाए, वही लोग

प्रदेश को लूटने और जातियों में बांटने के लिए जिम्मेदार हैं। मुर्शिदाबाद की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग, जिन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, माफियावाद और परिवारवाद से अपना साम्राज्य खड़ा किया, वही लोग अब मुर्शिदाबाद जैसे मामलों पर मौन हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनकी चुप्पी ने इन्हें चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है। पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, ठेके लेते थे, दंगे करवाते थे और महिलाओं व व्यापारियों को परेशान करते थे। लोग त्योहारों पर सशंकित रहते थे। अब यूपी में त्योहार शांतिपूर्ण और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। जो हाल आज मुर्शिदाबाद का है, वही कभी यूपी में मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों का हुआ करते थे। मुख्यमंत्री ने पूर्वी यूपी में इंसेफलाइटिस जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 40 वर्षों में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई।

जस्टिस अरुण पल्ली बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, शपथ ली

एजेंसी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने इनामी सहित 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री और उपकरण मिले हैं। यह कार्रवाई तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस के अनुसार सुरक्षाबलों के जवानों ने सर्चिंग के दौरान टेकमेटला के जंगल से विस्फोटक के साथ 7 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जांगला थाना में भी जवानों को बड़ी सफलता मिली है, यहां से 6 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा थाना नेलसनार से 9 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों के कब्जे से टिफिन बम, कार्डेक्स वायर, डेटोनेटर, बिजली का तार, बैटरी, खुदाई का औजार, नक्सल साहित्य, टंगिया जब्त किया गया है।

सभी की सहभागिता से प्रदेश के हरित और उज्जवल भविष्य का होगा निर्माण: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

एजेंसी

जैसलमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी की सहभागिता से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान की संकल्पसिद्धि हो सके। शर्मा जैसलमेर के पोकरण में रिन्यू पावर के 1.3 गीगावॉट पीक के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसलमेर की सुनहरी धरा पर स्थापित इस सोलर प्लांट से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कार्यों को गति मिलेगी। इस सोलर

प्लांट से उत्पादित समस्त बिजली राजस्थान की वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को ऊर्जा निर्बाध रूप से मिल सकेगी तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक बेंचमार्क तैयार होगा।

बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला - कक्षा 9 से 12 के शिक्षक दिसंबर तक कर सकेंगे काम

● कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह सीमित राहत दी है।

एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए भर्ती अनियमितताओं के बावजूद इन शिक्षकों को दिसंबर 2025 तक कार्यरत रहने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी और विशेष परिस्थितियों में दी गई है, ताकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?: मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार

की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि - राज्य सरकार 31 मई 2025 तक नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करे।पूरी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाए। अगर यह शर्तें पूरी नहीं की गईं तो कोर्ट कड़ी कार्रवाई करेगा।

किन्हें नहीं मिली राहत?: जहां एक ओर शिक्षकों को अस्थायी रूप से काम करने की इजाजत दी गई है, वहीं ग्रुप ष्ट और ष्ठ के कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है।

घोटाले की पृष्ठभूमि

2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 25 हजार से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन बाद में इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धांधली के गंभीर आरोप लगे। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इन 25 हजार से अधिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, साथ ही भर्ती प्रक्रिया को 'हेरफेर और धोखे से भरा' करार दिया था।

क्यों दी गई है राहत?

राज्य सरकार ने छात्रों के हित में शिक्षकों को अस्थायी रूप से बनाए रखने की अपील की थी, ताकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह सीमित राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा बोर्ड के कार्यों पर जताई नाराजगी, कहा- केवल कागजों तक सीमित

एजेंसी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते सड़क हादसों में घायलों को समय से इलाज और मुआवजा मिलने की घटती संख्या पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागजों तक सीमित रह गया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है। सरकार की उदासीनता को लेकर दूसरा मुद्दा यह भी है कि बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी! यह अब तक स्पष्ट नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था। नियुक्तियों को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा

अनुमोदित किया जाना था। लेकिन अब तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। हिट एंड रन दुर्घटनाओं पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारों के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने उठाया है। देश में विभिन्न कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता नहीं मिलती। ऐसे मामले भी हैं, जहां पीड़ित घायल नहीं होते लेकिन वाहन में फंस जाते हैं। याचिकाकर्ता की मांग है कि ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जो दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करें। सरकार के वकील ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका में एक मांग यह है कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं में जिम्मेदारी तय करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। यह अत्यंत कठिन है, क्योंकि कई मामलों में यह पता लगाना संभव नहीं होता कि वास्तव में क्या हुआ था। सरकार के वकील ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश में एक विसंगति है कि मोटर वाहन अधिनियम के मामलों को 10 वर्षों के बाद समाप्त कर दिया जाता है। इससे यह स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना भरता है, तो उसका पैसा चला जाता है, लेकिन अगर वह मामला लंबित रहने देता है तो अंततः मामला समाप्त हो जाता है। यह एक अत्यंत विचित्र स्थिति है। ऐसे मामले जमा होते रहते हैं और फिर कहा जाता है कि बहुत अधिक मामले हैं, जुर्माना केवल 500 या 1000 रुपये है, इसलिए मामले बंद कर दिए जाएं।

राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे, ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण

एजेंसी

नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले सप्ताह दो दिन के अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। वे फैकल्टी सदस्यों और छात्रों से बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ÷कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका के रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। वे वहां भाषण देंगे और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्यों तथा छात्रों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि रोड आइलैंड जाने से पहले राहुल गांधी एनआरआई समुदाय के सदस्यों के साथ-साथ इंडियन ओवरसीज

कांग्रेस (आईओसी) के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में राहुल गांधी ने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा की थी।

जस्टिस बीआर गवई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे, 14 मई को लेंगे शपथ

एजेंसी
नई दिल्ली। जस्टिस बीआर गवई देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश भेजी है। जस्टिस खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई 14 मई को चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। जस्टिस गवई लगभग छह महीने तक चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। परम्परा के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं। सरकार सामान्यतया उस सिफारिश को मान लेती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। जस्टिस गवई देश के 52वें चीफ जस्टिस होंगे।जस्टिस गवई ने 16 मार्च, 1985 से वकालत शुरू की थी। वे 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट और 1990 से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। अगस्त, 1992 से लेकर जनवरी, 2000 तक उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में महाराष्ट्र सरकार के वकील के तौर पर काम किया। 14 नवंबर, 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 24 मई, 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। जस्टिस गवई 23 नवंबर तक देश के चीफ जस्टिस होंगे।

दिल्ली में हर 70 पार बुजुर्ग को मिलेगा 'आयुष्मान कार्ड',अप्रैल के अंत तक लागू होगी योजना

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अप्रैल के अंत तक 70 साल से अधिक उम्र के सभी के लोगों के लिए 'आयुष्मान कार्ड' लॉन्च करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के विधायक और अधिकारी मौजूद थे। यह पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को साल भर में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना है, ताकि वे माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में इलाज करा सकें। बैठक का उद्देश्य आयुष्मान कार्डों का क्रियान्वयन और वितरण करने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आरोग्य मंदिर खोलने पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सालों के इंतजार के बाद दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना मिली है और इसे लागू करने के लिए आज हम बैठक कर रहे हैं, ताकि सभी कार्ड जल्दी से बनकर जनता तक पहुंच सकें। सभी विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इसका लाभ देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल को सीएसआर के तहत मिले महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण

नई दिल्ली। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ ईस्ट और मैकॉबर बीके प्राइवेट लिमिटेड ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल को कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत सीएसआर योगदान के माध्यम से अस्पताल को महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण दिए गए, जिनमें एक वेंटिलेटर, फेटोस्कोप और 2 कलर डॉप्लर अल्ट्रासाउंड मशीनें शामिल हैं। अस्पताल परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप बंसल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण उपकरण अस्पताल की सेवाओं को और मजबूत करेंगे, जिससे यहां देखभाल चाहने वाले हजारों रोगियों को समय पर और जीवन रक्षक हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद मिलेगी। सरकारी अस्पतालों को उन्नत चिकित्सा तकनीक से लैस करके, कॉर्पोरेट सहयोगी न केवल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं, बल्कि वंचित समुदायों की भलाई में भी सीधे योगदान देते हैं। यह पहल नैदानिक सटीकता को मजबूत करेगी, बेहतर रोगी निगरानी सुनिश्चित करेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार करेगी।

मुवक्किल को लेकर एसईएम कोर्ट में चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। कृष्णा नगर स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट में मुवक्किल को लेकर वकीलों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लात-घूंसे चलाए। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। शाहदरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि इस मामले में कृष्णा नगर थाने में दोनों ओर से गैर इरादतन हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस एक मामले में आरोपित को पेश करने पहुंची थी। आरोपित से किसी वकील ने पैरवी करने की डील कर ली थी लेकिन कुछ देर बाद दूसरे वकील ने पैरवी की डील ले ली।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा सीएसआईआर के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने नौवहन परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में एक बड़ी सफलता के रूप में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन समुद्री पोत की सराहना की है। वह आज यहां वैज्ञानिक और सीएसआईआर की चल रही पहलों और उपलब्धियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में सीएसआईआर निदेशालयों के सभी प्रमुख, सीएसआईआर के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार शामिल हुए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से उत्पन्न एक बड़ी सफलता बताते हुए खुलासा किया कि देश का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत बाद में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले बड़े समुद्री जहाजों या अन्य जहाजों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें सीएसआईआर द्वारा सक्षम आधारभूत

कार्य के आधार पर केपीआईटी द्वारा निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल-आधारित ड्राइवट्रेन है। सीएसआईआर के महानिदेशक डॉ. एन. कलईसेलवी ने सीएसआईआर की वर्तमान शोध गतिविधियों, हालिया तकनीकी प्रगति और उद्योग के साथ सहयोगात्मक जुड़ाव का ब्योरा पेश किया। चर्चा के दौरान मंत्री ने सीएसआईआर के वैज्ञानिक प्रयासों को प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। मंत्री ने सीएसआईआर-न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआईटीएलआई) की सराहना की और इसे सार्वजनिक-निजी क्षेत्र में सहयोगी नवाचार की एक अनूठी मिसाल बताया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने एनएमआईटीएलआई कार्यक्रम के तहत समर्थित दो हालिया सफलताओं की विशेष रूप से सराहना की। पहला है सीएसआईआर-टेक्नोस रमन स्पेक्ट्रोमीटर (सीटीआर-300 और सीटीआर-150) का विकास और व्यावसायीकरण, जिसे सीएसआईआर-एडवांस्ड मैटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसआईआर-एएमपीआरआई), भोपाल और मेसर्स टेक्नोस इंस्ट्रूमेंट्स, जयपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से हासिल किया गया है। जनवरी 2022 में विपणन के लिए स्वीकृत ये उच्च श्रेणी के रमन स्पेक्ट्रोमीटर भारत की वैज्ञानिक उपकरण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं।

अब तक देशभर में स्वदेशी रमन स्पेक्ट्रोमीटर की ग्यारह यूनिट आपूर्ति की जा चुकी हैं, जो इस स्वदेशी तकनीक को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि दूसरी प्रमुख सफलता उद्योग-आधारित एनएमआईटीएलआई कार्यक्रम के तहत ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास था।

निर्वाचन आयोग ने शुरू कीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां, बीएलए को दिया जा रहा प्रशिक्षण

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने इसके मद्देनजर बिहार के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के मान्यता प्राप्त 10 राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बीएलए को संबोधित किया। बीएलए को उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई।बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि-रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दिल्ली में 1008 संस्कृत सम्भाषण शिविरों का आयोजन 23 अप्रैल से 3 मई तक

एजेंसी
नई दिल्ली। संस्कृत भारती दिल्ली में 1008 संस्कृत सम्भाषण शिविरों का आयोजन 23 अप्रैल से तीन मई तक करने जा रही है। ये सभी शिविर निःशुल्क होंगे और इनका आयोजन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सामुदायिक स्थलों जैसे कि आरडब्ल्यूए, आश्रम, धर्मशाला, आर्य समाज मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गुरुकुल आदि में किया जाएगा। इस आयोजन में संस्कृत अकादमी दिल्ली उनका सहयोग करेगी। संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री जयप्रकाश गौतम और दिल्ली प्रांत अध्यक्ष डॉ. वागीश भट्ट ने कांस्टीट्यूशन क्लब में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी साझा की। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा, सांसद मनोज तिवारी, संस्कृत भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री जयप्रकाश गौतम और दिल्ली प्रांत अध्यक्ष डॉ. वागीश भट्ट ने अपने विचार साझा किए। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सभी नागरिकों से संस्कृत सम्भाषण शिविरों में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह केवल भाषा सीखने का अवसर नहीं है बल्कि अपनी

जड़ों से जुड़ने का अद्वितीय अवसर है। भाजपा सासंद मनोज तिवारी ने कहा कि अब तक हमने 'अंग्रेजी सीखो' जैसे अभियान देखे हैं लेकिन यह पहली बार है, जब हम इतने भव्य रूप में 'संस्कृत सीखो' अभियान देख रहे हैं। संस्कृत संस्कृति से जुड़ने का माध्यम है–यह कठिन नहीं, बल्कि प्राचीन होते हुए भी आधुनिक है।

ईडी की ताजा कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, सिंघवी बोले- कोई धनशोधन नहीं हुआ

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर ईडी की ताजा कार्रवाई को केंद्र की भाजपा सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध और गैर कानूनी करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इस मामले में कोई धन शोधन नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के ज्वलंत मुद्दों और समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भाजपा के इशारे पर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि एजेएल कारोबार के दौरान वित्तीय संकट में आ गई। नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्र को यही कंपनी चलाती है। कांग्रेस ने समय-समय पर नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र और एजेएल को कर्ज देकर इनके ऋणों का भुगतान किया, जो कि करीब 90 करोड़ रुपये थी। ऐसे में सवाल उठा कि एजेएल का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, जिसमें तय हुआ कि इसे ऋण मुक्त कंपनी बनाया जाए। ऐसे में इस कंपनी के 90 करोड़ के कर्ज को यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को ट्रांसफर किया गया- जो नई कंपनी थी। ये कर्ज कागजी रूप से ट्रांसफर हुआ, यानी जो कर्ज पहले कांग्रेस का था, वो अब यंग इंडिया लिमिटेड का हो गया था। सिंघवी ने कहा कि यंग इंडिया नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी (सेक्शन 8 के तहत) बनाई गई। इसके शेयर होल्डर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बने। इसके अलावा शेयर होल्डर और डायरेक्टर सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा बने। ऐसे में उस कर्ज को हिस्सेदारी में बदला गया। यानी एजेएल के शेयर यंग इंडिया को इश्यू हो गए, जिससे यंग इंडिया, एजेएल की 90-99त्न शेयर होल्डर बन गई लेकिन इसमें न पैसा ट्रांसफर हुआ, न संपत्ति। इस मामले में बहुत ही अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। इस कंपनी से कितना भी प्रॉफिट बने लेकिन एक भी पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते- सेक्शन-8 के तहत ये सीधे तौर पर प्रतिबंधित है। इसके अलावा इससे कोई सैलरी, कोई भत्ता भी नहीं दिया गया और न ही कोई संपत्ति खरीदी और बेची गई। इन संपत्तियों का मालिक अभी भी एजेएल ही है, सिर्फ उसकी शेयर होल्डिंग अब यंग इंडिया की है और यंग इंडिया में कुछ निदेशक हैं, जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता, तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई? नेताद्वय ने सवालिया लहजे में कहा कि इस केस में आरोप यह है कि शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके अलावा, पैसा और एजेएल की संपत्तियों को निदेशकों और गांधी परिवार ने हड़प लिया है लेकिन सवाल है कि किस निदेशक ने कुछ खरीदा-बेचा या लिया। अगर पैसा मिला, संपत्ति गई तो मनी ट्रेल कहां है? अपराध की आय कहां है? जब एजेएल की संपत्ति उसी की है। एजेएल की संपत्ति कभी यंग इंडिया को ट्रांसफर नहीं हुई। कानूनन जब तक यंग इंडिया वो संपत्तियां नहीं खरीदता है।

वक्फ एक धार्मिक ट्रस्ट है, सरकारी एकाधिकार के खिलाफ कोर्ट से न्याय की आशा : मौलाना महमूद असद मदनी

एजेंसी
नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरुद्ध जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी सहित विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन पर आधारित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षों की दलीलें दो घंटे तक ध्यान से सुनीं। जमीअत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व (याचिका संख्या 317/2025) में प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने किया, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मंसूर अली खान हैं। वकीलों ने अदालत में वक्फ अधिनियम की कई कमियों को उजागर किया, विशेष रूप से वक्फ के मूल ढांचे में बदलाव, वक्फ के लिए पांच साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त, वक्फ बाय-यूजर की की समाप्ति और गैर-मुस्लिमों को वक्फ परिषद और बोर्ड में सदस्य बनाना शामिल हैं। यह ऐसी मूलभूत कमियां हैं जो भारतीय संविधान के मूल प्रावधानों के विरुद्ध हैं। इसके साथ इनके कारण वक्फ की शरई स्थिति प्रभावित हो रही है। अदालत को बताया गया कि वक्फ बाय-यूजर की समाप्ति की वजह से चार लाख संपत्तियां प्रभावित होंगी। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहर के महत्व की इमारतें जैसे जामा मस्जिद का दर्जा भी खतरे में पड़ जाएगा। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वक्फ बाय-यूजर के आधार पर मान्य संपत्तियों को गैर-अधिसूचित किया गया तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे और बड़े परिवर्तन होंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस दौरान ऐसे किसी भी कार्य से बचा जाए जो अपरिवर्तनीय प्रभाव के महत्व के हैं।अदालत के समक्ष यह बात रखी गई कि नए कानून के तहत कलेक्टर को भूमि की जांच के दौरान वक्फ के दर्जे को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है, जो मुस्लिम धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप के समान है। अदालत ने इस बात को भी ध्यान से सुना और इसकी गंभीरता को समझा।

एम्स कर्मचारी संघ ने की नड्डा से मुलाकात, वैवाहिक आधार पर स्थानांतरण नीति लागू करने का किया आग्रह

एजेंसी
नई दिल्ली। अखिल भारतीय एम्स कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वैवाहिक आधार पर स्थानांतरण नीति लागू करने का आग्रह किया है। इस संबंध में संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर उन्हें को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्रालय से एम्स और मंत्रालय के अधीन अन्य चिकित्सा संस्थानों के कर्मचारियों के लिए वैवाहिक आधार पर स्थानांतरण नीति लागू करने का आग्रह किया गया है। संघ का तर्क है कि ऐसी नीति को न लागू होने से महिला कर्मचारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष भेदभाव होता है, जो सामाजिक अपेक्षाओं और पितृसत्तात्मक मानदंडों से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप, महिलाएं अपनी नौकरी छोड़ देती हैं या कार्यबल से बाहर हो जाती हैं, जो गैर-भेदभाव और समान अवसर के उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। इस ज्ञापन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी कई कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 1986, 1997, 2004 और 2009 में जारी किए गए नियम शामिल हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ने 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप को किया रेखांकित, नवाचार और समावेशी विकास पर दिया जोर

एजेंसी
नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए 'विकसित भारत 2047' की परिकल्पना और उस तक पहुंचने की दिशा में उद्योगों की अहम भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया के केंद्र में है। ओम बिरला ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह समय भारत के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और नवाचार का युग है। उन्होंने कहा कि सरकार की विकासोन्मुख नीतियां आज भारतीय उद्योगों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, गति शक्ति, भारतमाला और उड़ान जैसी योजनाओं ने देश में मजबूत औद्योगिक आधारशिला रखी है। लोकसभा अध्यक्ष ने 'विकसित भारत 2047' के रोडमैप को विस्तार से बताते हुए कहा कि यह लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि का नहीं, बल्कि एक समावेशी, सतत और नवाचार-आधारित विकास का है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की व्यापारिक नीतियां आज वैश्विक मंच

पर देश की साख को बढ़ा रही है। भारत निवेश के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य बनकर उभरा है, जहां %ईज ऑफ डूइंग बिजनेस% अब एक नारा नहीं, बल्कि हकीकत बन चुकी है। बिरला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से भारत में पारदर्शिता और दक्षता को मिली मजबूती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन की बढ़ती प्रवृत्ति देश में आर्थिक समावेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिली है। ओम बिरला ने देश में स्टार्टअप कल्चर और महिला उद्यमिता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक नवाचार केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां युवा उद्यमी और महिला कारोबारी विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। उन्होंने पीएचडीसीसीआई के महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मंच महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसायिक कौशल को सशक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

दिल्ली में हर 70 पार बुजुर्ग को मिलेगा 'आयुष्मान कार्ड',अप्रैल के अंत तक लागू होगी योजना

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार अप्रैल के अंत तक 70 साल से अधिक उम्र के सभी के लोगों के लिए 'आयुष्मान कार्ड' लॉन्च करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के विधायक और अधिकारी मौजूद थे। यह पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को साल भर में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना है, ताकि वे माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में इलाज करा सकें। बैठक का उद्देश्य आयुष्मान कार्डों का क्रियान्वयन और वितरण करने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में आरोग्य मंदिर खोलने पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सालों के इंतजार के बाद दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना मिली है और इसे लागू करने के लिए आज हम बैठक कर रहे हैं, ताकि सभी कार्ड जल्दी से बनकर जनता तक पहुंच सकें। सभी विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इसका लाभ देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली के हर इलाके में 1,139 आरोग्य मंदिर खोलने के लिए जगह की पहचान का काम तुरंत शुरू करना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने समय बर्बाद किया और दिल्ली को नुकसान हुआ। अब हम नहीं चाहते कि और समय बर्बाद हो। हमारी सरकार आज से इस पर काम करना शुरू कर देगी। सभी आयु वर्ग के 70 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र होंगे। यह कार्ड हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देता है, जिसमें 1500 से ज्यादा चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार शहर भर में 1,139 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बना रही है। ये आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में किया प्रदर्शन

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की जब्ती के विरोध में पार्टी द्वारा आज विभिन्न राज्यों में शक्ति प्रदर्शन किया गया। पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये प्रदर्शन केंद्र की मोदी सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के निरंतर अभियान का हिस्सा हैं।

कांग्रेस के आह्वान पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में राज्यों की राजधानियों में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों और जिलों में केंद्र सरकार के कार्यालयों के समक्ष आयोजित विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। वेणुगोपाल ने दावा किया कि आज के विरोध प्रदर्शन 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस समितियों द्वारा समन्वित किए गए, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, केरल, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों, फ्रंटल संगठन के नेता और वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24, अकबर रोड स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस

कमेटी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहां से ईडी कार्यालय जाने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हुआ। उसके बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और लक्षद्वीप प्रदेश कांग्रेस समितियों ने 17 और 18 अप्रैल को अपना विरोध प्रदर्शन निर्धारित किया है। यह सामूहिक कार्रवाई और विशाल भागीदारी हमारे संकल्प की पुष्टि है - सत्य, न्याय और भारत के संविधान के लिए खड़े होने की।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक कर्तव्य है। कांग्रेस पार्टी अनुशासन और साहस के साथ इस लड़ाई का नेतृत्व करना जारी रखेगी। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, हमारा विश्वास मजबूत है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग है।

ड्रग्स तस्करी के मामले में नाइजीरियन समेत दो गिरफ्तार

एजेंसी
नई दिल्ली। दक्षिण जिला पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में शामिल नाइजीरियन समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान संजय उर्फ सनम तथा चुकुनोन्सो उर्फ प्रिंसनी के रूप में हुई है। दोनों के पास 89.20 ग्राम हेरोइन व 3.29 ग्राम मेथमफेटामाइन (एमडी) बरामद किया गया है। गिरफ्तार संजय सोशल मीडिया के माध्यम से नाइजीरियन गैंग के संपर्क में आया था। दक्षिण जिले के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) के सूचना मिली थी कि एक नाइजीरियन गैंग दिल्ली-एनसीआर में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। सूचना को पुख्ता करने के बाद एएटीएस प्रभारी उमेश यादव की देखरेख में पुलिस टीम ने एमबी रोड पर जाल बिछाया कर संजय को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर महरौली से नाइजीरियन चुकुनोन्सो उर्फ प्रिंसनी को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से हेरोइन व मेथमफेटामाइन (एमडी) ड्रग्स बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि संजय सोशल मीडिया के जरिए नाइजीरियन नागरिक के संपर्क में आया था।

एनसीईआरटी की नकली किताबें बेच रहा कारोबारी गिरफ्तार

नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड (एएटीएस) ने एनसीईआरटी की नकली किताबें बेच रहे एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान अरविंद गुप्ता (33) के रूप में हुई है। अरविंद समयपुर बादली इलाके में नकली तरीके से छापी गई पुस्तकों को बेच रहा था। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर अलग-अलग कक्षाओं की 4091 पुस्तकें बरामद की हैं। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि दिल्ली की अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस में एनसीईआरटी की नकली किताबें छप रही हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में भी इनको छापा जा रहा है।

संपादक की कलम से

नीतीश कुमार का नारी विरोधी चेहरा

समाजवादी परिवार का हिस्सा रहने के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि समतावादी और सुशासन की रही है लेकिन इन दिनों जो उनका व्यवहार और नीतियां सामने आ रही हैं, वे इस बात को उजागर करने के लिये काफी हैं कि भीतर से वे नारी विरोधी हैं और रुढ़िगत पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता से खुद को बहुत अलग नहीं कर पाये हैं। कुछ ही महीनों में उनके राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें उनकी जनता दल यूनाइटेड पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हावी हो रही है और आगामी सरकार बनाने के लिये जैसी महत्वाकांक्षाएं न सिर्फ पाले बैठी है वरन उसका खुलकर इजहार भी कर रही है, वह भी नीतीश बाबू की परेशानी का एक कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की चचाएं जारी हैं। यदि उनके बारे में बन रही इस आशय की धारणाएं सही हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो यह भी देखा जाना चाहिये कि क्या उनका स्त्री विरोध इस मानसिकता का परिणाम तो नहीं है?

हाल ही में वे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिये विधान परिषद में जिस भाषावली का उपयोग कर रहे हैं वह उनके पद की गरिमा के प्रतिकूल और प्रजातंत्र के खिलाफ है। इन बयानों ने यह भी साबित किया है कि नीतीश कुमार का चेहरा चाहे प्रगतिशील नेता का हो लेकिन भीतरी तौर पर वे उस व्यापक भारतीय समाज का हिस्सा हैं जो अमूमन महिलाओं के प्रति वास्तविक सम्मान नहीं रखता। नीतीश कुमार अपने नारी विरोधी नजरिये का कई बार परिचय दे चुके हैं। याद हो कि जब कुछ समय के लिये जेडीयू तथा राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने प्रजनन प्रक्रिया को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने इसके लिये खेद जताते हुए खुद की ही भर्त्सना की थी। भरे सदन में उनके इस बयान पर विपक्ष, खासकर भाजपा की महिला विधायकों ने काफी विरोध किया था, जो हर तरह से वाजिब था। तब और अब में दो साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। कहते हैं कि तभी से नीतीश कुमार का व्यवहार असंतुलित सा हुआ दिखता है। हाल ही में एक कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान हो रहा था, तो वे अपने बाजू में खड़े मुख्य सचिव से बात करने लगे और उनके टोकने पर भी सीधे खड़े न होकर सामने किसी का अभिवादन करते नजर आये। उनका यह वीडियो देश भर में वायरल हुआ है जिसे देखकर लोगों का कहना था कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का मामला दर्ज होना चाहिये।

विधान मंडल के जारी बजट सत्र में उनकी राबड़ी देवी से कई बार बहस हुई है। यह कोई नयी बात नहीं लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, वह आश्चर्यजनक है। जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया वह असंसदीय तो हैं ही, अमर्यादित भी। पिछले दिनों नीतीश ने राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए कहा था- 'इनके पति को इस पद से हटाया गया, इसलिए ही वह मुख्यमंत्री बन पाई थीं।' उल्लेखनीय है कि जब राबड़ी देवी के पति लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के मामले पर मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था तो राबड़ी देवी ने वह पद सम्हाला था। फिलहाल वे विधान परिषद की सदस्य हैं। मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान आरक्षण पर गर्मागर्म बहस हो रही थी। राबड़ी देवी जब कुछ कहने के लिये उठीं, तो नीतीश कुमार ने उन्हें डपटते हुए कहा- 'अरे बैठो अपनी कुर्सी पर! पार्टी तोहरे हसबैंड का है, तोहरा कुछ नहीं। बैठा तू!' राबड़ी देवी ने विरोध जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में वह अपने 8 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर बोल सकती हैं, तो नीतीश ने मगही भाषा में बेहद अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, 'छोड़ा ना, तोहरा कुछ मालूम है?' मुख्यमंत्री ने आगे उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि 'पार्टी इसके हसबैंड का है, इ बेचारी तो ऐसे ही आ गई है।'

नीतीश कुमार की इस तरह की अशालीन भाषा का कारण उन पर पड़ रहा दबाव भी बतलाया जाता है। वे शायद इस खौफ में जी रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उनका हश्र वैसा ही न हो जाये जैसा कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे का हुआ है। पहले समर्थन देकर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया लेकिन उनके बल पर चुनाव जीतकर भाजपा के देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गये। वैसे भी भाजपा की प्रदेश इकाई तो कह ही चुकी है कि 'पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी।' इसलिये हाल ही में नीतीश कुमार राज्य भर का अकेले दौरा कर रहे हैं जबकि जेडीयू नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस का हिस्सा है। वे यह तैयारी कर रहे हैं कि भाजपा द्वारा धोखा मिलने पर वे अकेले चुनाव लड़ें। यह टास्क अपने आप में किसी को डराने या परेशान करने के लिये काफी होना चाहिये। इसके अलावा अनेक मामले हैं जिन्हें लेकर नीतीश घिरते जा रहे हैं। पहला तो है विशेष राज्य का दर्जा न मिलना जिसके आकर्षण में वे राजद के साथ गठबन्धन तोड़कर एनडीए में वापस चले गये थे। फिर, उनके कोर वोट बैंक दलितों, ओबीसी व मुसलमानों को भाजपा से दुश्वारियां मिलने के बावजूद उन्हें भाजपा के साथ जुड़े रहकर साथियों की नाराजगी व अपमान झेलना पड़ रहा है।

लेकिन सियासत की इन तमाम बातों से ऊपर उठकर सवाल यह है कि नीतीश कुमार या उनके जैसे कई और नेता किसी स्त्री के राजनीति में आगे बढ़ने पर सहज क्यों नहीं रह पाते हैं। राबड़ी देवी खुद से राजनीति में आईं या अपने पति के कहने पर आईं, यह किसी और की चिंता का विषय नहीं है। राबड़ी देवी के कार्यकाल की आलोचना नीतीश कुमार कर सकते हैं, लेकिन उनके राजनीति में होने पर कुछ कहना हर लिहाज से गलत है। नीतीश कुमार जब राबड़ी देवी पर कुछ न जानने का कटाक्ष कर रहे थे, तो वे एक स्त्री के साथ-साथ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री को भी अपमानित कर रहे थे।

मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस

प्रमोद भार्गव

कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी। दरअसल, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों का ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे।

रिजिजू ने इस मुद्दे को बारी-बारी से संसद के दोनों सदनों में उठाया। इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ह्यकांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परंतु कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऐसा करने जा रही है।

संविधान बदलने का बयान संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति ने दिया है, जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है। यही नहीं, कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी युवाओं का हक मारकर मुसलमानों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया था। जबकि हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई जगह नहीं है। अतएव इस तरह के प्रयास संविधान निमार्ताओं की देशहित से जुड़ी इच्छाओं के विरुद्ध हैं। बावजूद कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म आधारित आरक्षण देने के तुष्टिकरण से जुड़ा खेल निरंतर खेलती आ रही है।

कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति की रही है। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने चार बार आंध्रप्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। दरअसल, यह कांग्रेस का ह्यपायलट प्रोजेक्टह्य था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की की मंशा हमेशा रही है लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते इस मंशा को पलीता लगता रहा है। इस आरक्षण को लेकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर आपील को खरिज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से यह और स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए कि उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया ? कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या इस तरह कोटे में उप कोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा ? दरअसल, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्म के आधार परह्न आरक्षण का लाभ संविधान के विरुद्ध बताया था। दिसम्बर 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन कुटिल चतुराई से ओबीसी के कोटे में खासतौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया था। इसे आंध्र उच्च न्यायालय ने अस्वीकारते हुए साफ किया था कि कोटा के अंतर्गत उप कोटा दिए जाने का प्रावधान अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दिया गया है। इसे कानूनी रूप देते हुए कहा गया है कि ह्यअल्पसंख्यकों से संबंधितह्न और ह्यअल्पसंखयकों के लिएह्न जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था। क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। बहरहाल, न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस का मुस्लिमों को लुभाने वाले नुस्खे पर पानी फिर गया था।

वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, उनको बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत, अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती। खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में केवल पूंजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालत करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे। यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खोलने के लिए तैयार कराई गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता।

इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट इसी भेद को दूर करने की पैरवी करती है।

वर्तमान समय में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है,

धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है। परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केन्द्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं। इस नाते ह्यअल्पसंख्यक श्रेणीह्न का अधिकार पा लेने के क्या राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक निहितार्थ हैं, इन्हें समझना मुश्किल है। यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर जैन धर्मावलंबियों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाती है।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का आधार जिस मिश्र आयोग को बनाया गया था, उसका गठन ह्यजांच आयोग के तहतह्न नहीं हुआ था। दरअसल, इस रपट का मकसद केवल इतना था कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर व पिछड़े तबकों की पहचान कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सहित अन्य जरूरी कल्याणकारी उपाय सुझाये जाएं, जिससे उनका सामाजिक स्तर सम्मानजनक स्थिति हासिल कर ले। इस नजरिये से सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों का औसत अनुपात बेहद कम है। गोया संविधान में सामाजिक और शैक्षिक शब्दों के साथ पिछड़ा शब्द की शर्त का उल्लेख किये बिना इन्हें पिछड़ा माना जाकर अल्पसंख्यक समुदायों को 15 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें से 10 फीसदी केवल मुसलमानों को और पांच फीसदी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिए जाने का प्रावधान तय हो। शैक्षिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण की यही व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। यदि इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आती है तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण की जो 27 प्रतिशत की सुविधा हासिल है

कुआँ सूखने पर ही पता चलता है पानी की कीमत

-डॉ. सत्यवान सौरभ

एक सुदूर घाटी में बसे गांव में एक झरना था जिसे जीवन धारा कहा जाता था। पीढ़ियों तक ग्रामीणों ने इसका उपयोग किया, लेकिन जब आधुनिक सुविधाएं आईं, तो यह उपेक्षित हो गया। एक साल, भीषण सूखे ने झरने को सुखा दिया, और तभी ग्रामीणों को इसकी कीमत का एहसास हुआ। यह कहानी दशार्ती है कि हम अक्सर किसी चीज के महत्व को तब तक नहीं समझते जब तक वह खत्म नहीं हो जाती। पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, संबंध और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये हमेशा बने रहेंगे, परंतु जब यह संकट में होते हैं, तभी हम उनकी कीमत समझते हैं। जीवन की क्षणभंगुरता हमें वर्तमान का आदर करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे नल से पानी की सतत आपूर्ति को हम सामान्य मानते हैं, वैसे ही हम अपनों, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को भी हल्के में लेते हैं।

जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो हम उनकी कद्र करना छोड़ देते हैं। अरस्तू के नैतिक दर्शन के अनुसार, जागरूकता और संतुलन ही सच्चे गुणों को जन्म देते हैं। भरे कुएं का पानी हमें कृतज्ञ नहीं बनाता, परंतु पानी की कमी हमें उसकी महत्ता सिखाती है। 1930 के दशक की महामंदी ने लोगों को यह समझाया कि संसाधनों की उपलब्धता और कमी का चक्र कैसा होता है। ग्रीक त्रासदियों में अक्सर चरित्रों को जीवन का सच्चा अर्थ तब पता चलता है जब वे सब कुछ खो चुके होते हैं। शेक्सपियर के किंग लियर को प्यार की वास्तविकता तब समझ आई जब वह धोखा खा चुका था। महामारी ने भी हमें सामाजिक मेलजोल की अहमियत सिखाई। मानवता बार-बार संसाधनों का दुरुपयोग करती है और फिर संकट के समय उन्हें बचाने का प्रयास करती है। नीत्शे की शाश्वत पुनरावृत्ति की अवधारणा बताती है कि जब तक हम सच में नहीं सीखते, हम वही गलतियाँ दोहराते हैं। 1930 के डस्ट बाउल संकट ने कृषि को नुकसान पहुँचाया, जिससे सबक लेकर सुधार हुए, लेकिन समय के साथ लोग फिर लापरवाह हो गए।

उपयोगितावादी दर्शन कहता है कि किसी चीज का मूल्य उसकी उपयोगिता से निर्धारित होता है। जल की वास्तविक कीमत उसकी उपलब्धता के अनुसार बदलती है। उप-सहारा अफ्रीका में पानी की कमी ने जल संरक्षण के नए समाधान उत्पन्न किए। इसी तरह, जब कोई संसाधन दुर्लभ हो जाता है, तब उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जल संकट सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। पारिस्थितिक दर्शन बताता है कि हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। अरल सागर का सूखना इसका उदाहरण है, जिससे सामाजिक और आर्थिक संकट पैदा हुए। यदि हम संसाधनों को संरक्षित नहीं करते, तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। धार्मिक और दार्शनिक परंपराएँ बताती हैं कि वंचना मूल्य की गहरी समझ देती है। रमजान के उपवास लोगों को भोजन की कीमत और जरूरतमंदों की स्थिति का एहसास कराते हैं। इसी तरह, कठिनाइयाँ हमें जीवन की असली जरूरतों का महत्व सिखाती हैं।

मानव अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है, और जल संकट इस निर्भरता को दशार्ता है। फुकुशिमा परमाणु आपदा ने भी दिखाया कि तकनीकी विकास के बावजूद हम प्राकृतिक शक्तियों के आगे असहाय हैं। यह हमें हमारे संसाधनों की सीमाओं का सम्मान करना सिखाता है। पानी जीवन देता है, परंतु बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं से विनाश भी ला सकता है। ताओवाद के अनुसार, जीवन विरोधाभासों से भरा है, और हमें संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए।

बार-बार समाज को झकझोरते सवेंदनहीन, अमानवीय फैसले

-प्रियंका सौरभ

17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसने कानूनी गलियारों से लेकर आम जनता तक सभी को हैरान कर दिया। मामला था नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कर दीं, जिन पर बवाल मच गया। देखते ही देखते यह मामला गरमाया और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए हाई कोर्ट की विवादास्पद टिप्पणियों पर रोक लगा दी और यूपी सरकार व केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। अब यह मामला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का विषय भी बन चुका है।

विवाद की जड़ क्या थी?

हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि पीड़िता के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा खोलने की कोशिश करना 'दुष्कर्म की कोशिश' की परिभाषा में नहीं आता। बस, यही बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ! कानून के जानकारों, सामाजिक कार्यकताओं और आम जनता ने इस पर सवाल उठाए। कई लोगों ने इसे यौन अपराधों के खिलाफ बनाए गए कड़े कानूनों को कमजोर करने वाला करार दिया। POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि इसने यह संकेत भी दिया कि शायद न्यायपालिका में कुछ बदलावों की जरूरत है।

न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता

यह कोई पहला मामला नहीं है जब न्यायपालिका के किसी फैसले ने विवाद खड़ा किया हो। इससे पहले भी कई ऐसे निर्णय सामने आए हैं, जिन्होंने यौन हिंसा से जुड़े मामलों में न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। कई बार पीड़ितों को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, और कई मामलों में फैसले इतने कमजोर होते हैं कि अपराधियों को इसका लाभ मिल जाता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका को यौन अपराधों के मामलों में अधिक जागरूक और संवेदनशील होने की जरूरत है। सिर्फ कानून की किताबों में लिखी धाराओं का पालन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट का जवाबी हमला

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गंभीरता से लेते हुए पाया कि इस तरह की टिप्पणियाँ समाज में गलत संदेश दे सकती हैं। इससे भविष्य में अन्य मामलों में भी गलत नजीर (precedent) बन सकती है। ऐसे में, शीर्ष अदालत ने फौरन हाई कोर्ट की विवादास्पद टिप्पणियों पर रोक लगा दी।

इसके अलावा, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया गया कि वे इस पर अपना पक्ष रखें। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकारें इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं।

सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध

यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा। महिला अधिकार संगठनों, वकीलों और सामाजिक कार्यकताओं ने इसे अन्याय करार दिया। ट्विटर से लेकर सड़क तक, इस फैसले का जमकर विरोध हुआ। ट्रेंड्स में #JusticeForVictims और #JudiciaryReform जैसे हैशटैग छा गए। लोगों का कहना था कि ऐसे फैसले यौन हिंसा के पीड़ितों का हौसला तोड़ सकते हैं और अपराधियों को बढ़ावा मिल सकता है। महिला संगठनों ने भी इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया और मांग की कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के फैसले समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बना सकते हैं।

क्या कहता है कानून?

भारतीय दंड संहिता (IPC) और ढडउरड अधिनियम के तहत यौन अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं। इनमें सजा के स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन कई बार अदालतों की व्याख्या इन मामलों में दोषियों को राहत देने का काम करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ढडउरड एक्ट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित न्याय मिल सके। सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी कानूनी खामियों को दूर करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। क्या हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह पलटा जाएगा? क्या आरोपी की जमानत रद्द होगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई नई गाइडलाइन जारी करेगा? यह मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली और उसकी संवेदनशीलता की परीक्षा भी बन चुका है।

समाज के लिए एक सीख

इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल उठता है झ्र क्या हमारी न्याय प्रणाली यौन अपराधों के मामलों में और अधिक संवेदनशील हो सकती है? या फिर ऐसे सवेंदनहीन, अमानवीय फैसले बार-बार समाज को झकझोरते रहेंगे?

गर्मियों में क्यों होता है फंगल इंफेक्शन, इससे कैसे करें बचाव

गर्मी के इस मौसम में कई प्रकार की बीमारियों के होने का रिस्क रहता है. गर्मी में स्किन डिजीज भी होती है. सबसे ज्यादा खतरा फंगल इंफेक्शन का रहता है. यह इंफेक्शन किसी भी उम्र में हो जाता है और अगर इलाज न हो तो शरीर के लिए खतरनाक भी बन सकता है. कारण यह है कि फंगल इंफेक्शन फैल सकता है. जो स्किन के लिए अच्छा नहीं है. गर्मियों मेंधूप, धूल मिट्टी से इस बीमारी का खतरा और ज्यादा बढ़ता है. फंगल इंफेक्शन क्यों होता है. इससे बचाव कैसे करें इस बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं.

गाजियाबाद में डमेटोलॉजिस्ट डॉ. सौम्या सचदेवा बताती हैं कि गर्मियों में तेज धूप और पसीने के कारण फंगल इंफेक्शन होता है. गर्मी में पसीना आता है औ यह कपड़ों में चिपक जाता है. इससे वहां फंगस पनप जाती है और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाता है. जिससे फंगल इंफेक्शन हो जाता है. गर्मी में फंगल इंफेक्शन के साथ-साथ ही स्किन इंफेक्शन का भी रिस्क होता है. इसमें स्किन पर दाने निकलने से लेकर, लगातार खुजली रहना और सफेद परत जमने जैसी समस्या आ सकती है.

स्किन इंफ्केक्शन से बचाव कैसे करें

स्किन इंफेक्शन से बचाव के लिए जरूरी है कि शरीर की साफ- सफाई का ध्यान रखे. कपड़े क्या पहनने का इसका भी ध्यान रखें. गर्मी में सिल्क और टेरीकोट कपड़े पहनने से बचें. कोशिश करें की सूती कपड़े पहनें. क्योंकि ये पसीने को सोंखते हैं जिससे फंगल इंफेक्शन होने का रिस्क कम रहता है. कपड़ों के साथ यह भी ध्यान रखें की लंबे समय तक धूप में न रहें और खुद को तेज गर्मी से भी बचाएं. डॉ सौम्या बताती हैं कि गर्मियों के मौसम में खानपान का ध्यान रखना भी जरूरी है. इस मौसम में ज्यादा पानी वाले फल खाएं. जैसे की तरबूज और खरबूज

अफ्रीकी राज्य में 'बापू' की प्रतिमा का अनावरण, यहां 100 से ज्यादा साल तक भारतीयों पर था प्रतिबंध

एजेंसी

स्टाकहोम । दक्षिण अफ्रीकी राज्य के एंग्लो-बोअर युद्ध संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह एक ऐसा राज्य है जहां पर रंगभेद कानून के चलते 100 साल से ज्यादा समय तक भारतीयों पर प्रतिबंध था। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता राम वांगी सुतार द्वारा बनाई गई कांस्य प्रतिमा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने संग्रहालय को दान की थी। प्रतिमा का अनावरण 11 अप्रैल को भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने 1899-1902 के एंग्लो-बोअर युद्ध में भारतीयों की भागीदारी की अब तक की अनकही कहानी पर एक वृत्तचित्र और एक किताब के साथ किया। 1994 में जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति चुने गए थे तो पहला ऑरेंज फ्री स्टेट भारतीयों को रंगभेद कानून द्वारा प्रतिबंधित करता था। ब्लूमफोंटेन में बने युद्ध संग्रहालय में दक्षिण अफ्रीकी एंग्लो-बोअर युद्ध की याद बनाया गया है। इस युद्ध में सभी नस्लों के दक्षिण अफ्रीकी शामिल थे। इनमें श्वेत, अफ्रीकी, रंगीन और भारतीय शामिल थे। ब्लूमफोंटेन में युद्ध संग्रहालय के निदेशक टोकी प्रीटोरियस ने कहा कि संग्रहालय ने इस प्रकाशन के माध्यम से दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों और भारत से आए लोगों दोनों की भागीदारी को मान्यता देने के लिए एक परियोजना शुरू की है।

दिलचस्प हुआ कनाडा चुनाव, ट्रंप की धमकी के बाद लिबरल पार्टी को मिली संजीवनी

टोरंटो। कनाडा में आम चुनाव के लिए 28 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी और भारी-भरकम टैरिफ लगाने के बाद कनाडा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। दरअसल कुछ समय पहले तक सत्ताधारी लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पिछड़ती नजर आ रही थी। इसके चलते जस्टिस ट्रूडो को भी पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी जगह मार्क कार्नी को पीएम बनाया गया था। अब ट्रंप की धमकी के बाद जिस तरह से लिबरल पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है, उसके बाद से पार्टी की लोकप्रियता में उछाल देखा गया है। यही वजह है कि लिबरल पार्टी जहां चुनाव में ट्रंप से सामना करने का मुद्दा उठा रही है, वहीं विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी बदलाव की मांग कर रही है। फ्रेंच लैंग्वेज लीडर्स की डिबेट के दौरान मार्क कार्नी और पिएरे पोएलीवरे का आमना सामना हुआ। इस दौरान पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि 'इस चुनाव में सवाल ये है कि कौन राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करेगा।' वहीं पिएरे पोएलीवरे ने बदलाव पर जोर दिया और कहा कि लोगों को लिबरल पार्टी को चौथा कार्यकाल नहीं देना चाहिए।

बिना नोटिस आव्रजन दर्जा खत्म हुआ तो अमेरिकी कोर्ट पहुंचा भारतीय छात्र

वाशिंगटन। अमेरिका से अप्रवासियों के निर्वासन का सिलसिला लगातार जारी है। मगर अब वीजा लेकर रह रहे लोगों को भी निर्वासित करने के लिए उनका आव्रजन दर्जा खत्म किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में अब अमेरिकी गृह विभाग और आव्रजन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बार मुकदमा चार छात्रों ने दर्ज कराया है। इसमें एक भारतीय छात्र चिन्मय देवरे भी शामिल है। छात्र का कहना है कि उसके आव्रजन दर्जे को बिना नोटिस और सूचना दिए समाप्त कर दिया गया। जबकि उनके खिलाफ न तो कोई मुकदमा है और न ही वे किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं। आव्रजन अधिकारियों की कार्रवाई से भारतीय छात्र चिन्मय देवरे समेत तीन अन्य छात्रों का करियर खतरे में पड़ गया है। मिशिगन के अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने छात्रों की ओर से दायर मुकदमे में कहा कि चिन्मय देवरे वेन स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक कर रहे हैं। वे 2004 में एच 4 आश्रित वीजा लेकर अपने परिवार के साथ अमेरिका आए। उन्होंने और उनके परिवार ने 2008 में अमेरिका छोड़ दिया। मगर 2014 में उनका परिवार वापस आ गया। मिशिगन में हाईस्कूल पूरा करने के बाद चिन्मय ने एच-4 स्थिति के तहत वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। जहां से वह 2021 से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक कर रहे हैं। चिन्मय ने मई 2022 में आवेदन किया और उन्हें एच-4 स्टेटस की उम्र खत्म होने पर एफ-1 छात्र का दर्जा पाने की अनुमति दे दी गई।

अब गाजा के बच्चों पर कुपोषण की मार, तीन हजार से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, नहीं मिल पा रहा खाना

नई दिल्ली। पहले से ही इस्राइल के हमले झेल रही गाजा की जनता अब एक नई समस्या से जूझ रही है। दरअसल गाजा में रह रहे लोगों में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। खासकर बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और मार्च महीने में ही तीन हजार से ज्यादा बच्चे कुपोषण के चलते अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। गौरतलब है कि हमास के साथ युद्धविराम समझौता टूटने के बाद इस्राइल ने गाजा में मानवीय मदद रोक दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फरवरी में 2027 बच्चे कुपोषण के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मदद मामलों की एजेंसी (ओसीएचए) ने ये आंकड़े जारी किए हैं।

'हम हिंदुओं से अलग', पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने उगला नफरती जहर, बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल गए

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की बुनियाद नफरत के आधार पर रखी गई और आज उसकी स्थिति दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है, लेकिन हैरानी है कि उसकी ये नफरती सोच अभी तक नहीं बदली है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर की है और कहा है कि हम हिंदुओं से अलग हैं। आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को सही ठहराया है। इतना ही नहीं पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ये भी दावा कर दिया है कि उनकी संस्कृति और विचारधारा बेहतर है। बुधवार को ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि 'हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हिंदुओं से हर मामले में अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति-रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं और हमारे विचार भी अलग हैं। हमारी महत्वकांक्षाएं अलग हैं और यही द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (टू नेशन थ्योरी) का आधार था। जिसमें माना गया कि हम दो देश हैं, एक नहीं।' आसिम मुनीर ने अपनी छोटी सोच दिखाते हुए विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को भी भारत और हिंदुओं से भेदभाव करना सिखाएं। मुनीर ने कहा कि 'हम एक देश नहीं हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश

को बनाने में काफी संघर्ष किया। हम जानते हैं कि इसकी कैसे रक्षा की जानी है। आपको अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे कभी भी पाकिस्तान की कहानी को न भूलें। न भूलें कि पाकिस्तान किस आधार पर बना ताकि उनका पाकिस्तान के साथ नाता कमजोर न हो सके। आसिम मुनीर यहीं नहीं रुके और विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से कहा कि 'वे इस बात को न भूलें कि वे बेहतर विचारधारा और बेहतर संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं।' पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर मुनीर ने कहा कि'क्या आतंकी हमारे देश से हमारी किस्मत छीन सकते हैं? जब 13 लाख की मजबूत भारतीय सेना, हमारे नहीं डरा सकती तो कुछ आतंकी क्या हमें हरा सकते हैं?' पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने बलूचिस्तान में बढ़ रहे विद्रोह पर कहा कि 'बलूचिस्तान पाकिस्तान का गर्व है और आपको लगता है कि आप इसे आसानी से ले सकते हैं? आपकी दस पीढ़ियां भी इसे नहीं ले पाएंगी। हम जल्द ही आतंकियों को हरा देंगे। 'द्वि राष्ट्र सिद्धांत का मुख्य आधार था कि हिंदू और मुसलमान अलग-अलग संप्रदाय हैं और ये साथ नहीं रह सकते। इसी सिद्धांत के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का बंटवारा कराया। टू नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान ने अपने इतिहास के ठुकराया और बाहर से आए आक्रमणकारियों और आक्रांताओं को अपना हीरो माना। पाकिस्तान ने अपनी किताबों में भी बच्चों को नफरत सिखाई। अब पाकिस्तान खुद अलगाववाद से जूझ रहा है।

काठमांडू में दो करोड़ के अवैध सोने- चांदी के गहने सहित नौ भारतीय गिरफ्तार

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के काठमांडू से दो करोड़ रुपये से अधिक के सोने और चांदी के गहने सहित नौ भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वह राजधानी के विभिन्न स्थानों सोना और चांदी की अवैध बिक्री कर रहे थे। काठमांडू पुलिस के प्रवक्ता अपील बोहरा कहा कि पुलिस कार्रवाई के दौरान छापा मार कर एक किलो 76.518 ग्राम सोना तथा एक किलो 845.429 ग्राम चांदी जब्त की गई है। जब्त किए गए सोने की कीमत एक करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि चांदी की कीमत 30 लाख रुपये है। इसके अलावा उनके कब्जे से 8 लाख 27 हजार रुपये नेपाली करेंसी और 91 हजार 700 रुपये भारतीय करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 30 वर्षीय नव नाथ बाकू कासिद, संदीप पोपट हजारे 20 वर्ष, अंसार दिलावर सिकलगर 22 वर्ष, सुरेश राजेश मदने 18 वर्ष, अरमान हनीफ इमांडया 21 वर्ष, मनोज सुभाष सकत 22 वर्ष, अमोल कुमार गोस्ले 38 वर्ष, सुनील मितकारी 20 वर्ष और सूरज नंदीवाली 20 वर्ष शामिल हैं।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी भारतीय नागरिक महाराष्ट्र से हैं और वर्तमान में काठमांडू में विभिन्न स्थानों पर रह रहे थे।

टैरिफ की मार से बेहाल कैलीफोर्निया ने ट्रम्प सरकार के खिलाफ किया मुकदमा

एजेंसी

कैलीफोर्निया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ की मार से अन्य देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका के राज्य भी काफी परेशान हैं। हालात यह हैं कि कैलीफोर्निया राज्य ने लगाए गए टैरिफ पर रोक के लिए संघीय अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। राज्य का आरोप है कि राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत प्रयोग किया है। इससे उनके राज्य ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की अर्थ व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बीते दनों डोनाल्ड ट्रम्प ने दस फीसदी से लेकर ऊंची दरों पर टैरिफ लगाए हैं। इस टैरिफ से अमेरिका के कमोवेश सभी राज्य परेशान हैं, लेकिन अभी कैलीफोर्निया खुलकर टैरिफ के विरोध में आ गया है। संघीय अदालत में दायर मुकदमे में कैलीफोर्निया स्टेट ने कहा कि संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति के पास इसका कोई अधिकार ही नहीं हैं।राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनामिक पावर्स एक्ट की दलील देकर टैरिफ लगाया है, जो कि गलत है। यह कानून राष्ट्रपति को उनके मन

मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया अमेरिका में सबसे अधिक सामान आयात करता है। यहां के 12 बंदरगाहों के जरिए 40 फीसदी आयात होता है। इसलिए टैरिफ लगाने से सबसे अधिक यह राज्य ही प्रभावित हुआ है। इस टैरिफ से राज्य की अर्थ व्यवस्था के साथ ही नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। उधर मामला अदालत तक जाने पर व्हाइट हाउस ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सरकारी प्रवक्ता कुश देसाई ने कैलीफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम से कहा कि उनके राज्य में अपराध चरम पर है। महंगाई की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उन्हें राज्य की समस्याओं पर ध्यान दें, न कि टैरिफ को रोकने के प्रयास करनी चाहिए। उनका यह कदम किसी भी सूरत में उचित नहीं कहा जा सकता।

दक्षिण अफ्रीका में अगवा अमेरिकी पादरी को पुलिस ने गोलीबारी के बाद बचाया

एजेंसी

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में एक प्रार्थना सभा के दौरान अगवा किए गए अमेरिकी पादरी जोशुआ सुलिवन को पुलिस ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। अपहरण के बाद हुई गोलीबारी में तीन संदिग्धों की मौत हो गई। टेनेसी से आए मिशनरी सुलिवन को मदरवेल टाउनशिप स्थित फेलोशिप बैपटिस्ट चर्च से चार हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया था। चर्च में प्रवचन के दौरान हमलावरों ने मण्डली के दो मोबाइल फोन चुराए और फिर सुलिवन को जबरन अपने साथ ले गए। कुछ घंटों बाद उनका वाहन लावारिस हालत में बरामद हुआ। दक्षिण अफ्रीका की विशेष पुलिस इकाई 'हॉक्स' ने संदिग्धों का पता लगाकर क्रामाग्जाकी नामक इलाके में छापेमारी की। पुलिस के अनुसार, संदिग्धों ने एक वाहन में बैठे-बैठे पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में तीव्र मुठभेड़ हुई। सुलिवन को उसी वाहन से सुरक्षित बचा लिया गया, जिसमें हमलावर सवार थे। उन्हें कोई चोट नहीं आई है और चिकित्सकीय जांच में भी उन्हें ठीक बताया गया है। जोशुआ सुलिवन

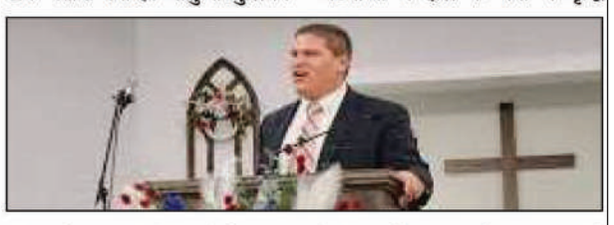

की मां टोन्या मॉर्टन रिंकर ने फेसबुक पर लिखा, मेरा बच्चा आजाद है। जोशुआ अब घर पर अपनी पत्नी मेगन और बच्चों के साथ है। उन्होंने सुलिवन को बड़े दिल वाले सज्जन व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। सुलिवन 2015 में पहली बार अपनी पत्नी के साथ दक्षिण अफ्रीका आए थे और बाद में चर्च-रोपण मिशन के तहत वहीं बस गए। वे स्थानीय भाषा खोसा में भी धाराप्रवाह बोलने में सक्षम हैं। उनके चार जैविक और दो गोद लिए हुए बच्चे हैं। उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका में अपहरण की घटनाओं में हाल के वर्षों में वृद्धि देखी गई है। 2024 में 17,000 से अधिक अपहरण के मामले दर्ज हुए। हालांकि, अधिकांश मामलों में कारण फिरौती नहीं, बल्कि वाहन अपहरण और डकैती होते हैं। सुलिवन के अपहरण का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को राहत की सांस दी है।

अमेरिका में करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में भारतीय मूल का डॉक्टर दोषी करार, 130 साल तक की हो सकती है सजा

एजेंसी

काबुल। अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां भारतीय मूल के एक अमेरिकी डॉक्टर नील के आनंद को अमेरिका में स्वास्थ्य सेवा में बड़े स्तर पर धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी पाया गया है। 48 वर्षीय आनंद को मरीजों को जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक दवाएं देकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में दोषी पाया गया है। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में डॉ आनंद पर और भी कई सारे गंभीर आरोप लगे, जिनमें स्वास्थ्य सेवा और वायर फ्रॉड की साजिश, स्वास्थ्य सेवा में धोखाधड़ी के 3 मामले, मनी लॉन्ड्रिंग का 1 मामला, अवैध मौद्रिक लेनदेन के 4 मामले प्रतिबंधित दवाओं को बांटने की साजिश जैसे आरोप शामिल है।

130 साल की हो सकती है सजा: बता दें कि दोषी पाए जाने के बाद डॉ. आनंद को इन मामलों में

19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। साथ ही उन पर लगे आरोप के चलते उन्हें 130 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। हालांकि, अंतिम सजा का फैसला संघीय अदालत का न्यायाधीश करेगा, जो अमेरिकी कानूनों और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा।

कैसे करता था हेराफेरी, समझिए: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉ. आनंद ने अपने क्लिनिक में मरीजों को गुडी बैग्स (दवाइयों से भरे बैग) देने की योजना बनाई थी। ये दवाएं उनके इन-हाउस फार्मेसी से दी जाती थीं। ये दवाएं न तो मरीजों को चाहिए थीं और न ही वो लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें दवाएं दी गईं ताकि बीमा कंपनियों से पैसा वसूला जा सके। उन्होंने अमेरिका की प्रमुख बीमा योजनाओं जैसे मेडिकेयर, ओपीएम, इंडिपेंडेंस ब्लू क्रॉस और एंथम को फर्जी दावे भेजे। इससे कुल मिलाकर इन कंपनियों से 2.3 मिलियन डॉलर (लगभग 19 करोड़ रुपये) वसूले गए।

नशे की दवाई बांटने के भी आरोप: साथ ही मामले में यह भी सामने आया कि आनंद ने ऑक्सीकोडोन जैसी नशे की दवा बिना किसी वैध कारण के मरीजों को दी। इतना ही नहीं, बिना लाइसेंस वाले मेडिकल इंटर्न्स ने आनंद के पहले से साइन किए हुए खाली पर्चों पर दवाइयां लिखीं। इस योजना के तहत आनंद ने सिर्फ 9 मरीजों के लिए ही 20,850 ऑक्सीकोडोन की गोलियां लिख दीं।

चार हजार लोगों के ई-वालेट ऐप हैक कर 01 करोड़ रुपये चुराने वाला 22 वर्षीय युवक गिरफ्तार

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को 4000 लोगों के ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म से एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक 22 वर्षीय राहुल बूढ़ा है। काठमांडू पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कालीमाटी से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक अंगुर जी.सी. ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक ने विभिन्न फिशिंग लिंक भेजकर 4,000 लोगों के ऑनलाइन भुगतान कंपनी ई-सेवा के खातों से 01 करोड़ 20 लाख रुपये चुराए हैं। पुलिस का कहना है कि वह एसएमएस के जरिए द अलर्ट और एटी अलर्ट जैसे फिशिंग लिंक भेजता था और लिंक खोलने के बाद उसके ई-सेवा एप को हैक कर पैसे चुरा लेता था। पूछताछ में आरोपित युवक ने बताया कि वह एसएमएस में भेजे गए लिंक के जरिए पैसे उड़ाता था। आरोप है कि व्यक्ति को लिंक खोलने के लिए मजबूर करके ई-सेवा तक पहुंच बनाता और उसमें रहे पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसका ऐप ही डिलीट कर देता था। एसपी जिसी ने बताया कि सारे पैसों को वह पशुपति ग्लोबल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यापारी खातों में जमा करता था।

ईयू ने सात देशों को घोषित किया 'सुरक्षित', शरणार्थियों की वापसी प्रक्रिया होगी तेज़

एजेंसी

ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने सात देशों को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य शरण मांगने की प्रक्रिया को तेज करते हुए अनियमित प्रवासियों की वापसी को सुगम बनाना है। इस सूची में कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, भारत, मोरक्को और ट्यूनिशिया शामिल हैं। यूरोपीय आयोग ने कहा कि इन देशों को सुरक्षित मूल देश मानने से इन देशों के नागरिकों द्वारा यूरोप में किए गए शरण के दावों को तेजी से खारिज किया जा सकेगा क्योंकि यह माना जाएगा कि इन दावों में आमतौर पर ठोस आधार नहीं होता। ईयू के प्रवासन आयुक्त मैग्नस ब्रूनर ने कहा, कई सदस्य देश शरणार्थी आवेदनों के बड़े बैकलॉग से जूझ रहे हैं। इस बाबत तेजी से निर्णय लेने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है।

हालांकि, मानवाधिकार संगठनों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की है। यूरो-मेड राइट्स नामक समूह ने कहा कि इस सूची में शामिल कई देशों में मानवाधिकार हनन और नागरिकों के लिए सीमित सुरक्षा जैसी गंभीर चिंताएं हैं। उन्होंने कहा, इन देशों को सुरक्षित कहना भ्रामक और खतरनाक है। यूरोपीय आयोग ने यह स्पष्ट किया कि हर शरण आवेदन को व्यक्तिगत रूप से जांचा जाएगा और मौजूदा सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वास्तविक शरणार्थी को अनुचित रूप से खारिज न किया जाए। इस प्रस्ताव को लागू होने से पहले यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की मंजूरी मिलनी आवश्यक है। हालांकि, इटली, डेनमार्क और नीदरलैंड्स जैसे देशों के दबाव के चलते इस दिशा में तेजी लाई गई है। इटली के आंतरिक मंत्री माटेओ पियानटेडोसी ने इस कदम को ÷इटली सरकार की एक बड़ी सफलता÷ बताया। बतादें कि यह कदम ऐसे समय में आया है जब ईयू में अनियमित प्रवेश मामलों में 2024 में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन प्रवासन नीति पर राजनीतिक दबाव लगातार बना हुआ है।

राष्ट्रपति ने संसद का बजट सत्र 25 अप्रैल को बुलाया

एजेंसी

काठमांडू । नेपाल सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा संघीय संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सरकार की सिफारिश पर दोनों सदनों के लिए 25 अप्रैल को दोपहर एक बजे बैठक का आह्वान किया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 93, उपधारा (1) के अनुसार, 25 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर एक बजे संघीय संसद के दोनों सदनों के सत्र का आह्वान किया है। सुबह ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद राष्ट्रपति को संसद के बजट सत्र बुलाने की सिफारिश करने का फैसला किया गया था। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता शैलजा रेगमी भट्टराई ने प्रेस वक्तव्य जारी कर इसकी जानकारी

दी है। नेपाल के संविधान में देश का आम बजट 29 मई तक सदन में पेश करने की बात उल्लेख है। उससे पहले सरकार के करीब एक दर्जन से अधिक विधेयक संसद में लंबित है, जिसके आगामी बजट सत्र में पारित होने की संभावना है। सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कहा कि शिक्षकों से संबंधी विधेयक के अलावा सोशल मीडिया रेगुलेटरी विधेयक, संवैधानिक परिषद विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं।

टैरिफ वार से अमेरिका में बढ़ेगी महंगाई, सेंट्रल बैंक के प्रमुख बोले- आगे की राह मुश्किल

एजेंसी

कोलंबो। ट्रंप प्रशासन द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ गया है और इसका असर विभिन्न उद्योगों पर पड़ा है। अब अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ वार के चलते महंगाई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन में जो नीतिगत बदलाव किए गए हैं, उनकी वजह से केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की परेशानी बढ़ सकती है। शिकागो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जेरोम पॉवेल ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं, वे उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं और इससे बनी अनिश्चितता की स्थिति अर्थव्यवस्था पर स्थायी असर डाल सकती है। पॉवेल ने कहा कि सरकार ने बहुत ही नीतिगत बदलाव किया है और इस बारे में क्या किया जाए, इसका हमें कोई अनुभव नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पास रोजगार बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी है। पॉवेल ने चेतावनी दी है कि टैरिफ वार के चलते रोजगार और महंगाई दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है।

नेपाल में नई सरकार गठन को लेकर प्रचंड के बयान से राजनीति गरमाई

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड' के उस बयान के बाद राजनीति गरमा गई है, जिसमें उन्होंने ओली सरकार के जल्द ही गिरने और सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का दावा किया था। अब सत्तारूढ़ दल के नेताओं की अपनी ही सरकार की लगातार आलोचना से विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान ओली सरकार के खिलाफ जागरण अभियान चला रहे माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने बुधवार की सुबह नवलपरासी जिले से एक बयान दिया था कि देश में नई सरकार के गठन को लेकर उनकी पार्टी और सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है। प्रचंड यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि जल्द ही ओली सरकार का पतन होगा और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार गठन होने वाला है। प्रचंड के इस बयान के बाद बुधवार की शाम को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों कांग्रेस और एमाले के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक से नेपाली कांग्रेस पार्टी के दो बड़े पदाधिकारी नदारद रहे, जिससे गठबंधन में दरार आने की चर्चा को और अधिक बल मिला। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और सरकार संचालन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के संयोजक रहे पूर्ण बहादुर खड़का और पार्टी के महामंत्री गगन थापा के इस बैठक में सहभागी नहीं होने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई। बुधवार को देर रात तक चली इस बैठक में शामिल

गृह मंत्री रमेश लेखक ने बैठक के बाद बाहर आकर मीडिया को बताया कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है और मिल कर सरकार संचालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं की ओर से सरकार की सार्वजनिक आलोचना किए जाने को गठबंधन धर्म के विपरीत बताया। सुबह से ही गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल की अलग-अलग बैठक हुई। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा ने सुबह ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों और सरकार में शामिल मंत्रियों की संयुक्त बैठक कर गठबंधन में कोई भी समस्या नहीं रहने का संकेत दिया है। इस बैठक में सहभागी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. प्रकाश शरण महत ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं को हिदायत दी गई है कि कोई भी सरकार की आलोचना न करे। जिसको भी अपनी बात कहनी है वो पार्टी की बैठकों में या गठबंधन की बैठक में रखे। उधर ही प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें गठबंधन में आई समस्या पर विचार किया गया। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की तरफ से सरकार के कामकाज की सार्वजनिक आलोचना के कारण अविश्वास का संकट जैसा दिख रहा है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी आपसी मतभेद हैं, उनको बैठक में सुलझा लिया जाएगा।

ड्रीम स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप फुटबॉल 2025: बालिका वर्ग में झारखंड एफए और बालक वर्ग में पंजाब एफसी ने जीता खिताब

एजेंसी

गोवा। गोवा के प्रसिद्ध रायया स्पोर्ट्स ग्राउंड में ड्रीम स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप फुटबॉल 2025 का भव्य फाइनल मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक फाइनल में देशभर से आई युवा फुटबॉल प्रतिभाओं ने अपना दमखम दिखाया। बालिका वर्ग में झारखंड एफए ने खिताब अपने नाम किया, जबकि बालक वर्ग में पंजाब एफसी ने अपना खिताब बरकरार रखा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के समापन समारोह में भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुब्रत पॉल और बाईचुंग भूटिया समेत गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे, परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो, पूर्व मुख्यमंत्री व विधायक दिगंबर कामत, आईपीएस वर्षा शर्मा (डीआईजी, गोवा पुलिस) और गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कैटानो फर्नांडिस ने शिरकत की। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। बालिका वर्ग के नेशनल फाइनल में झारखंड एफए और ओडिशा एफए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। झारखंड ने 20वें मिनट में अनामिका सांगा के एकमात्र गोल की बदौलत 1-0 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। ओडिशा की टीम बराबरी की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन झारखंड की कप्तान चांदनी कुमारी की अगुवाई में रक्षापंक्ति ने अंत तक बढ़त कायम रखी।

कोच और कप्तान ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने पर खुशी जताई

झांसी। हॉकी पंजाब के कोच राजिंदर सिंह और कप्तान हार्दिक सिंह ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने पर खुशी जताई है। कोच राजिंदर सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट हमारे लिए अच्छा रहा और हमने बढ़िया प्रदर्शन किया। कप्तान हार्दिक ने कहा कि फाइनल में लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम जीत से बेहद खुश हैं। हॉकी पंजाब ने उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर प्रतिष्ठित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। हॉकी पंजाब ने 2023 में यह टूर्नामेंट जीता था। पिछले संस्करण में वे हॉकी महाराष्ट्र से क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए थे। इस बार कप्तान हार्दिक सिंह और कोच राजिंदर सिंह की अगुआई में हॉकी पंजाब ने फिर से चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। हॉकी पंजाब को पूल चरण में हॉकी मध्य प्रदेश से अपनी एकमात्र हार का सामना करना पड़ा था लेकिन फाइनल में अपनी गलतियों को सुधारते हुए हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। क्वार्टर फाइनल में टीम ने हॉकी हरियाणा पर 3-2 से जीत हासिल की।

रहाणे ने ली हार की जिम्मेदारी, केकेआर टीम को हार से लेना चाहिये सबक

चंडीगढ़। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पंजाब किंग्स से मिली हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि टीम को इस हार से सबक लेना चाहिये। यहां महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ रोमांचक कम स्कोर के मुकाबले में 16 रन से मिली हार की रहाणे ने जिम्मेदारी ली और कहा कि टीम को इस हार से सबक लेकर आगे के मैचों जीतने का प्रयास करना चाहिये। केकेआर की ओर से शानदार गेंदबाजी की गयी और पंजाब किंग्स को 111 रन बनाने दिये। केकेआर की ओर से हर्षित राणा ने तीन विकेट और सुनील नारायण तथा वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लिए। केकेआर लेकिन 112 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी तरह से लड़खड़ा गई। रहाणे ने हार की जिम्मेदारी ली और कहा कि टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के अनुकूल रूप से बल्लेबाजी नहीं की है। मैच के बाद कप्तान रहाणे ने कहा, हमने एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में वास्तव में खराब बल्लेबाजी की, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। गेंदबाजों ने जिस तरह से वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया, पंजाब की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को 111 पर रोक दिया।

हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल में सिल्वर जीतकर आए जैद और सुंदरम का किया सम्मान

इटारसी। झांसी में संपन्न हुई 15 वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2025 में मध्यप्रदेश की हॉकी टीम उपविजेता रही है। इस टीम में इटारसी डीएचए के दो प्लेयर सुंदरम सिंह राजावत और मो.जैद खान ने भी प्रतिनिधित्व किया। इन दोनों प्लेयर का आज शाम यहां गांधी स्टेडियम में जिला हॉकी संघ ने सम्मान किया। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण विभाग से प्राप्त खेल सामग्री फीडर सेंटर के बच्चों को वितरित की गई। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टी प्रतीक राव, आईएएस, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, ओलंपियन विवेक सागर प्रसाद, सीनियर प्लेयर एससी लाल, डीएचए के अध्यक्ष भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, डीएचए के कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी, जयराज सिंह भानू, कोषाध्यक्ष सर्वजीत सिंघ सैनी, उपाध्यक्ष डॉ. ताविश अरोरा, अरुण रावर्ट, इदरीश खान, मयंक जेम्स, साजिद मलिक ने किया।

इंटर मिलान ने बायर्न म्यूनिख को 4-3 से हराकर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बनाई जगह

एजेंसी

मिलान। इंटर मिलान ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 के क्वार्टरफाइनल के रोमांचक मुकाबले में बायर्न म्यूनिख को 4-3 के एग्रीगेट स्कोर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। रात सान सिरो स्टेडियम में हुए दूसरे लेग का मुकाबला 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन पहले लेग में मिली 2-1 की जीत के चलते इटालियन चैंपियन इंटर ने अंतिम-4 में प्रवेश किया। अब इंटर का मुकाबला सेमीफाइनल में बार्सिलोना से होगा।

लौटारो और पावार्ड के गोल ने इंटर को दिलाई बढ़त

बारिश और तेज़ हवाओं के बीच खेले गए इस मुकाबले में पहले हाफ तक दोनों टीमों के बीच गोल नहीं हुआ। हालांकि, दूसरे हाफ में मुकाबला रोमांचक हो उठा। बायर्न के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने 52वें मिनट में गोल कर स्कोर बराबर कर दिया और मुकाबले को नई जान दे

दी। इसके बाद इंटर के कप्तान लौटारो मार्टिनेज ने 58वें मिनट में गोल दागकर इंटर को फिर से बढ़त दिलाई। महज तीन मिनट बाद, बेंजामिन पावार्ड ने एक शानदार हेडर से गोल कर इंटर को निर्णायक बढ़त दिला दी।

डायर ने दिलाई उम्मीद, लेकिन समर ने बचाई जीत: 75वें मिनट में एरिक डायर ने बायर्न के लिए हेडर के जरिए गोल कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। इसके बाद बायर्न ने बराबरी के लिए लगातार दबाव बनाया। स्टॉपेज टाइम में हैरी केन का हेडर इंटर के गोलकीपर यान समर ने शानदार तरीके से रोक लिया और यहीं से इंटर की जीत तय हो गई।

सान सिरो में दिखा अलग नज़ारा, टेबल सपना ज़िंदा

इंटर मिलान के फैंस ने टिकट की बढ़ी कीमतों के विरोध में शुरुआती 20 मिनट तक स्टेडियम में सन्नाटा बनाए रखा। इसके बाद फैंस ने जोरदार शोर और गानों से अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। इंटर अब 2010 के जोसे मोरिन्हो युग की तरह एक बार फिर से सीरी ए, चैंपियंस लीग और इटालियन कप ट्रेबल जीतने की ओर बढ़ रही है। टीम इस समय इटली की लीग टेबल में नेपोली से तीन अंकों की बढ़त बनाए हुए है और डोमेस्टिक कप के सेमीफाइनल में एसी मिलान से भिड़ने वाली है।

आईपीएल मैच : 20 अप्रैल को इन्दू नाग देव के दर पंहुचेंगी एचपीसीए

एजेंसी

धर्मशाला। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के सफल आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 20 अप्रैल को इन्दू नाग के दर पंहुचेंगी। इस दौरान एचपीसीए द्वारा मंदिर में सुबह हवन और पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर में एक भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में किसी भी स्तर के मैच होने से पूर्व एचपीसीए हर बार धर्मशाला के खनियारा स्थित बारिश के देवता इन्दू नाग के दर पंहुचकर पूजा और हवन का आयोजन करती है। वहीं मैच के सफल आयोजन के बाद इन्दू नाग का आभार जताने के लिए भी पूजा की जाती है। मैच के दौरान किसी भी तरह से मौसम का खलल न पड़े इसके लिए ही इन्दू नाग देवता के मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन होता है। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने बताया कि 20 अप्रैल को स्थानीय देवता इन्दू नाग के मंदिर में पूजा और हवन किया जाएगा तथा बाद में भंडारे का भी आयोजन भी किया जाएगा।

धर्मशाला में आईपीएल के खेले जाएंगे तीन मैच

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इस सीजन के तीन आईपीएल मैच खेले जाने हैं। पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड धर्मशाला में पंजाब चार मई को अपना पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेलेगा। वहीं आठ मई को पंजाब की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगी। यह दोनों मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होंगे। वहीं 11 मई को पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच दिन में साढ़े तीन बजे से मैच शुरू होगा।

आर्सेनल 16 साल बाद चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में , रियल मैड्रिड को 5-1 के एग्रीगेट स्कोर से हराया

एजेंसी

मैड्रिड। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने चैंपियंस लीग 2024-25 सीज़न में शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड को क्वार्टरफाइनल में 5-1 के एग्रीगेट स्कोर से मात दी। बुधवार रात हुए दूसरे लेग के मुकाबले में आर्सेनल ने 2-1 से जीत दर्ज कर 16 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब उनका मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) से होगा। आर्सेनल ने पिछले हफ्ते लंदन में खेले गए पहले लेग में 3-0 की बड़ी जीत दर्ज की थी, जिसका फायदा उन्हें मैड्रिड में मिला। मैच की शुरुआत से ही आर्सेनल ने रक्षात्मक रणनीति अपनाई और रियल मैड्रिड के आक्रामक खेल को ज़्यादा मौके नहीं दिए। पहले हाफ में आर्सेनल को पेनल्टी का मौका मिला जब वीएआर की मदद से रियल के राउल असेंसियो द्वारा मिकेल मेरिनो को खींचने का मामला पकड़ में आया। हालांकि, साका का पेनल्टी किक थिबो कोर्टुआ ने रोक लिया। इस चूक के बाद साका ने दूसरे हाफ में 65वें मिनट में शानदार वापसी की और टीम के लिए पहला गोल दागा।साका के गोल के दो मिनट बाद ही विलियम सलीबा की गलती का

फायदा उठाते हुए विनीसियस जूनियर ने बराबरी का गोल कर रियल को थोड़ी उम्मीद दी। लेकिन, स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे के चोटिल होकर मैदान छोड़ने से रियल मैड्रिड की मुश्किलें और बढ़ गईं। मैच के इंजरी टाइम में गेब्रियल मार्टिनेली ने आर्सेनल के लिए दूसरा और निर्णायक गोल कर रियल मैड्रिड की वापसी की उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दीं। पिछले सीज़न में चैंपियंस लीग और ला लीगा डबल जीतने वाली रियल मैड्रिड इस बार अपनी लय में नहीं दिखी। पहले लेग में 3-0 की हार के बाद टीम मैड्रिड में भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। स्टार स्ट्राइकर एम्बाप्पे भी पूरी तरह लय में नहीं दिखे और आखिरी मिनटों में चोटिल होकर बाहर हो गए। आर्सेनल ने अब तक चैंपियंस लीग इतिहास में सिर्फ तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पिछली बार 2009 में टीम इस मुकाम पर पहुंची थी।

सुरुचि-सौरभ की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता स्वर्ण

एजेंसी

नई दिल्ली। लीमा (पेरू) में चल रही आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक मुकाबले में सुरुचि-सौरभ की जोड़ी ने चीन की कियानसुन याओ और काई हू की जोड़ी को 17-9 के अंतर से पराजित किया। दोनों भारतीय निशानेबाजों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य भेदा और खिताबी मुकाबला अपने नाम किया।

कांस्य पदक मुकाबले में मनु-रविंदर हारे

कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में भारत की मनु भाकर और रविंदर सिंह की जोड़ी को चीनी निशानेबाजों चियानके मा और यीफान झांग के हाथों 6-16 से हार का सामना करना पड़ा।

सुरुचि का दूसरा स्वर्ण, सौरभ को भी व्यक्तिगत कांस्य

18 वर्षीय सुरुचि ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस

स्पर्धा में उन्होंने अपनी सीनियर और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीतकर एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन का प्रमाण दिया। सौरभ के लिए यह वर्ष 2022 के बाद किसी आईएसएसएफ विश्व कप में पहला व्यक्तिगत पदक है।

चयन चरण में भी दमदार प्रदर्शन

सुरुचि और सौरभ की जोड़ी ने 580 अंकों के साथ स्वर्ण पदक मुकाबले में स्थान सुनिश्चित किया। इस दौरान सुरुचि ने सौरभ से दो अंक अधिक प्राप्त किए। चयन चरण में चीनी जोड़ी याओ कियानसुन और हू काई 585 अंकों के साथ शीर्ष पर रही थी।

संजू सैमसन की चोट ने राजस्थान रॉयल्स की हार में डाला बड़ा असर

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के दौरान राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन चोटिल हो गए और रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। राजस्थान रॉयल्स की 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन जब शानदार लय में बल्लेबाज़ी कर रहे थे, तभी छठे ओवर में लेग स्पिनर विप्रज निगम की गेंद पर कट शॉट लगाने की कोशिश में उनकी पसलियों में खिंचाव आ गया। दर्द के चलते वह तुरंत मैदान पर ही अपने साइड को पकड़ते नज़र आए। अगली गेंद नो-बॉल थी और फ्री हिट पर सैमसन ने शॉट तो खेला लेकिन दौड़ नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने फिजियो की मदद

ली और अंततः रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले गए। उस वक्त सैमसन 19 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे थे और यशस्वी जायसवाल के साथ 5.3 ओवर में 61 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके थे। संजू सैमसन चोट के बाद दोबारा बल्लेबाज़ी के लिए नहीं उतरे। सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाज़ी करने आए, लेकिन टीम केवल 11 रन ही बना सकी। मैच के बाद सैमसन ने अपनी चोट को लेकर कहा, फिलहाल ठीक लग रहा है। बस वापसी करने के लिए तैयार नहीं था। कल देखेंगे कैसा रहता है। उन्होंने माना कि स्कोर चेज़ किया जा सकता था लेकिन मिचेल स्टार्क की बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाज़ी ने खेल का रुख बदल दिया। राजस्थान रॉयल्स को आखिरी तीन ओवर में 31 रन की ज़रूरत थी और आठ विकेट शेष थे। लेकिन मिचेल स्टार्क ने 18वें ओवर में सेट बल्लेबाज़ नितीश राणा (51) को आउट कर बाज़ी पलट दी। 20वें ओवर में उनकी यॉर्कर्स ने सुपर ओवर तक मामला पहुंचा दिया। सुपर ओवर में भी स्टार्क ने अपनी धारदार गेंदबाज़ी से दिल्ली को जीत दिलाई। इस हार के बाद राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गई है। टीम ने अब तक सात में से केवल दो मैच ही जीते हैं। उनके अगले तीन मुकाबले 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जाएंट्स, 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ होंगे।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार रखें खेल ढांचा: खेल मंत्री

एजेंसी

नैनीताल। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा स्टेडियम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने सर्व प्रथम स्टेडियम के प्राकृतिक आपदा की चपेट में आये क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम की प्रगति की भी समीक्षा की और इसे जल्द से जल्द सुचारू करने को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त खेल मंत्री ने फुटबॉल ग्राउंड, ताइक्वांडो, मल्टीपरपज हॉल और स्विमिंग पूल का भी निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की खेल लिगेसी पॉलिसी तैयार हो रही है, तब तक स्कूली बच्चों को इन खेल सुविधाओं का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खेल अवस्थापनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब हमारे भावी खिलाड़ी और बच्चे इन पर अभ्यास करके अपने कौशल को निखारेंगे।उन्होंने खेल विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी स्टेडियम व अन्य खेल सुविधाओं को इस तरह से सुचारू रखें कि इन पर जल्द ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप स्तर के खेलों का आयोजन कराये जा सकें। उन्होंने गौलापार में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय (स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) की तैयारी में तेजी लाने के निर्देश दिए।

आईपीएल 2025: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हराया

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 32वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया है। आईपीएल के 18वें सीजन के पहले सुपर ओवर में राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 11 रन बनाए। जिसके जवाब में दिल्ली ने केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स की मदद से संदीप शर्मा की 4 गेंदों पर ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ दिल्ली अंक तालिका में 10 अंकों के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई है। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। दिल्ली के लिए अभिषेक पोरेल ने 49 और केएल राहुल ने 38 रन बनाए। जबकि ट्रिस्टन स्टब्स (नाबाद) और अक्षर पटेल ने 34-34 रन का

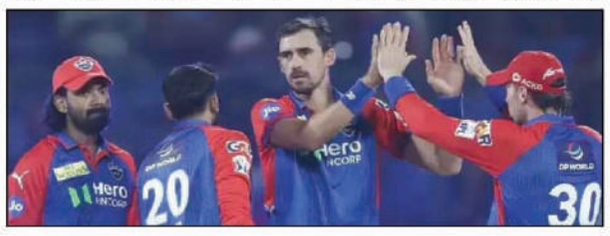

योगदान दिया। वहीं आशुतोष शर्मा ने नाबाद 15 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर को दो विकेट मिले, जबकि महीश तीक्ष्णा एवं वनिंदु हसरंगा के खाते में एक-एक सफलता रही। दिल्ली की ओर से मिले 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की तूफानी शुरुआत रही। कप्तान संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने 6 ओवर में 63 रन बनाए। हालांकि तभी सैमसन रिटायर्ड हर्ट हो गए। सैमसन ने 31 रन बनाए। इसके बाद रियान पराग ने क्रीज पर उतरे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं सके और आठ रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नीतीश राणा ने यशस्वी का अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 36 रन जोड़े तभी यशस्वी 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तब राणा ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर 49 रन जोड़े और टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। इश बीच नीतीश राणा भी अपना अर्धशतक पूरा कर आउट हो गए, उन्होंने 51 रन की पारी खेली। आखिर के छह गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 9 रन की जरूरत थी और जुरेल के साथ शिमरॉन हेटमेयर क्रीज पर थे, लेकन मिशेल स्टार्क की धाकड़ गेंदबाजी और एक के बाद एक यॉर्कर ने राजस्थान की उम्मीदों पर पारी फेर दिया। स्टार्क ने सिर्फ 8 रन दिए, जिससे राजस्थान 20 ओवर में 188 रन ही बना सकी। तब सुपर ओवर की ओर खेल मुड़ गया, जहां दिल्ली ने बाजी मारी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मिचेल स्टार्क ने 1-1 विकेट लिया।

बीसीसीआई को महिला टीम के लिए मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट, कोच की तलाश

बेंगलुरु। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय सीनियर महिला टीम के लिए मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। बीसीसीआई ने बैंगलुरु में स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुख्य फिजियोरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए आवेदन मांगे है। चयन के बाद कोच और मुख्य फिजियोरेपिस्ट को मैचों और टूर्नामेंटों के दौरान सीनियर महिला टीम के साथ यात्रा करना भी आवश्यक है। मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट आवेदकों के पास खेल या मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर योग्यता के साथ ही कम से कम 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।

अमरोहा के हर्ष सिंह का उप्र की अंडर-14 क्रिकेट टीम में चयन

एजेंसी

मुरादाबाद। उ प्र क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक व पूर्व रणजी खिलाड़ी विजय गुप्ता ने बताया कि जनपद अमरोहा के ग्राम शेखपुरा निवासी हर्ष सिंह का उत्तर प्रदेश की अंडर-14 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि हर्ष सिंह रुक्मणी क्रिकेट एकेडमी में 5 साल से कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी व कोच मोहम्मद हसीन की देख-रेख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। डिस्ट्रिक स्पोर्टस एसोसिएशन मुरादाबाद के संयुक्त सचिव नितिन गुप्ता ने बताया कि हर्ष सिंह विकेट कीपर बल्लेबाज़ हैं। कानपुर कमला क्लब में लगे चयन कैंप में हर्ष सिंह ने दो मैच खेले जिसमें हर्ष ने पहले मैच में नाबाद 119 और दूसरे मैच में नाबाद 59 रन की बेहतरीन पारी खेली। जिसके चलते उनका उत्तर प्रदेश की अंडर-14 टीम में चयन किया गया है। हर्ष सिंह के पिता देवेंद्र सिंह ने बताया कि हर्ष सिंह 7 साल की उम्र से ही कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी व कोच मौहम्मद हसीन की देख रेख में क्रिकेट की बारीकिया सीख रहे हैं। आज चयन की जानकारी सुनकर बहुत खुशी हो रही है परिवार में खुशी का माहौल है हर्ष सिंह की कामयाबी का श्रेय उनके कोच को जाता है। जिन्होंने बचपन से बहुत मेहनत की है 7

साल की उम्र से से हॉस्टल में रहकर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है। हर्ष के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने बताया हर्ष टैलेंटेड प्लेयर है पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की टीम में शामिल होने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है इससे पहले भी वह दो बार उत्तर प्रदेश की अंडर-14 टीम के चयन हेतु फाइनल कैम्प में खेल चुका है। इस बार अच्छा प्रदर्शन किया दो मैच में शानदार प्रदर्शन किया और नाबाद 178 रन बनाकर टीम में जगह बनाई। इस दौरान रुक्मणी ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉ सिद्धार्थ मलिक ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की अकैडमी में खुशी का माहौल है। सभी साथी खिलाड़ियो को हर्ष सिंह से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

ऐतिहासिक जीत के बाद पोंटिंग ने की चहल की तारिफ, बोले- तुमने अपनी तरह गेंदबाजी की हम मैच जीत गए

एजेंसी

न्यू चंडीगढ़। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स ने 111 रन के सबसे कम स्कोर को डिफेंड कर ऐतिहासिक कारनामा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकआर) पर मिली इस जीत के लिए पंजाब के कोच रिकी पोंटिंग ने यजुवेंद्र चहल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अपनी तरह की गेंदबाजी कर चहल ने केकेआर के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी और पंजाब को जीत दिलाई। पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने चहल की जमकर तारीफ़ की। उन्होंने कहा, हमने इस हफ्ते तुमसे कहा था कि अपनी असली गेंदबाज़ी पर लौटो। और आज तुमने वही किया। अपनी तरह गेंदबाजी की और हमें मैच जिता दिया। पोंटिंग ने मार्को यानसन (3/17) और अर्शदीप सिंह (1/11) की भी सराहना की। उन्होंने कहा, अर्शदीप, तुम आमतौर पर नई गेंद से गेंदबाज़ी करते हो, लेकिन जब टीम ने तुमसे अलग भूमिका निभाने को कहा, तो तुमने पूरी जिम्मेदारी से प्रदर्शन किया। यही टीम भावना हम सबमें चाहिए। पोंटिंग ने बताया कि उन्होंने कप्तान से चर्चा करके यानसन से पहला ओवर करवाया क्योंकि वे पहले भी सुनील नारायण को जल्दी आउट कर चुके थे और यह रणनीति काम कर गई।

आईजीयू ने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्क्वाड कैंप का किया आयोजन

एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। देश के सर्वश्रेष्ठ युवा गोल्फरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय गोल्फ संघ (आईजीयू) द्वारा 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ग्रेटर नोएडा स्थित जेपी ग्रीन्स में राष्ट्रीय स्क्वाड कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप आगामी जर्मन इंटरनेशनल एमेच्योर चैम्पियनशिप (01 से 04 मई, बर्लिनर गोल्फ एंड कंट्री क्लब, जर्मनी) के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के तहत हो रहा है। इस कैंप में देशभर से चुने गए 10 प्रतिभाशाली एमेच्योर गोल्फर भाग ले रहे हैं। जिनके नाम अरिन आहूजा, रक्षित दहिया, सुखमन सिंह, कनव चौहान, वरुण मुथप्पा, अयन गुप्ता, जैवियर, दीपक यादव, संदीप यादव और विनम्र आनंद हैं। आईजीयू ने यह राष्ट्रीय स्क्वाड सिस्टम पिछले वर्ष पेरिस ओलंपिक से पूर्व शुरू किया था ताकि खिलाड़ियों को तकनीकी, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। इस अवसर

पर आईजीयू के महानिदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विभूति भूषण ने कहा, यह कैंप एक मजबूत और एकजुट राष्ट्रीय टीम के निर्माण की दिशा में अहम कदम है। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि मानसिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से फिट और टीम भावना से लैस खिलाड़ियों को तैयार करना है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करें। विभूति भूषण ने कहा कि कैंप को समग्र प्रशिक्षण पहल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें गोल्फ तकनीक के अलावा फिजियोथेरेपी, फिटनेस, खेल मनोविज्ञान और पोषण जैसे अहम विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही टीम भावना और सामूहिक प्रतिस्पर्धा की भावना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय गोल्फर सुखमन सिंह ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, आईजीयू द्वारा दी गई यह अवसर मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

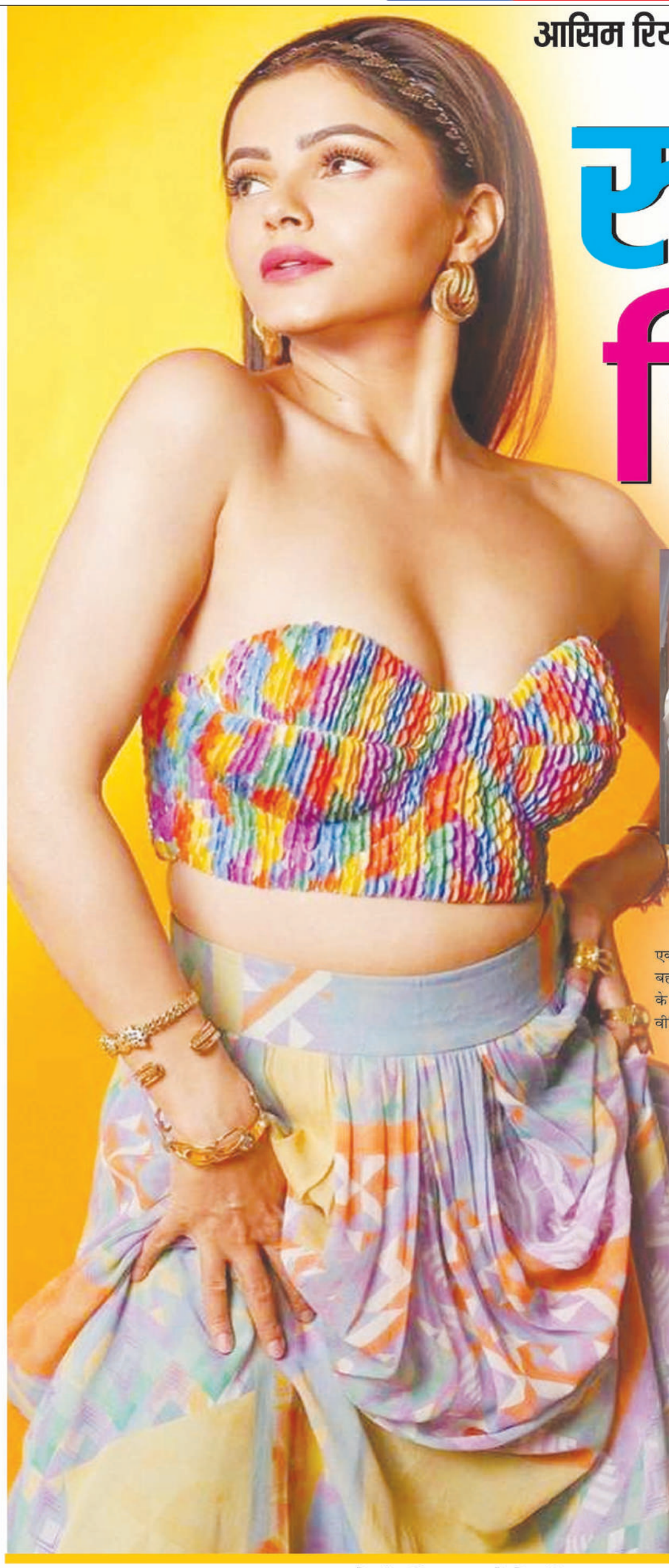

आसिम रियाज से शिखर धवन ने मंगवाई माफी,

रुबीना दिलैक

पर कमेंट से मचा था बवाल

ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहे नए शो 'वॉर ऑफ वर्ड्स' में दर्शकों को जमकर ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस शो में रुबीना दिलैक, आसिम रियाज, अभिषेक मल्हान के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे बड़े ही बेबाकी से अपनी राय सबके सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में शो का एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें रुबीना दिलैक और आसिम रियाज के बीच तीखी बहस देखने को मिली. इस बहस के बाद शो के होस्ट और मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन ने दोनों के बीच हस्तक्षेप करते हुए आसिम से कहा कि वो रुबीना से माफी मांगे.

वीडियो में हम देख सकते हैं कि आसिम रियाज, रुबीना दिलैक पर 'सीरियल' जैसा बर्ताव करने का आरोप लगा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये सीरियल नहीं है.आसिम की ये बात सुनकर रुबीना नाराज हो जाती हैं और वो, 'आसिमम वहां पर मत जाओ' कहते हुए बिग बॉस 13 के एक्स-कंटेस्टेंट को अपनी हद में रहने की चेतावनी देती हैं. इस प्रोमो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी आसिम रियाज के इस रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई है. एक तरफ जहां लोग आसिम पर निशाना साध रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ रुबीना दिलैक ने जिस तरह से आसिम के आरोपों का शांत रहकर जवाब दिया, उसके लिए दर्शक उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं. कई लोगों ने उन्हें इस शो की 'शेरनी' भी कहा है.

आसिम को मांगनी पड़ी माफी

रुबीना और आसिम में हुई बहस के बाद शो के होस्ट शिखर धवन ने मामले में हस्तक्षेप किया और आसिम रियाज को अपनी गलती का एहसास दिलाया. शिखर ने साफ शब्दों में कहा कि आसिम ने रुबीना से जो कुछ भी कहा, वो सही नहीं था और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. शिखर धवन की बात सुनकर आसिम रियाज ने अपनी सफाई दी और कहा कि उन्होंने गुस्से में ऐसा कह दिया था, उनका कोई गलत इरादा नहीं था. इसके बाद आसिम ने रुबीना से माफी भी मांगी, जिसे रुबीना ने समझदारी दिखाते हुए स्वीकार कर लिया.

रुबीना को मिला फैंस का साथ

सोशल मीडिया पर रुबीना दिलैक के फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. साथ ही वो आसिम रियाज के रवैये को 'अनावश्यक' और 'अनुचित' भी बता रहे हैं. सिर्फ रुबीना ही नहीं बल्कि शिखर धवन की भी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है. क्योंकि फैंस का कहना है कि उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ ये झगड़ा सुलझाया है.

कभी 1500 रुपये कमाने वाला वो एक्टर, जिसने सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड को बनाया दुल्हन, 800 करोड़ी फिल्म से हिला डाला बॉक्स ऑफिस

बात आज एक ऐसे एक्टर की जिसका बचपन मुंबई के चॉल में बीता. उसकी पहली सैलरी महज 1500 रुपये थी. उसने 10 साल पहले हिंदी सिनेमा में अपनी कदम रखे थे. धीरे-धीरे वो सफलता के रथ पर सवार होता गया और फिर उसकी लाइफ में एंट्री हुई हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक की. इसके बाद इस एक्टर ने बड़े पर्दे पर धूम मचा दी.क्या आप समझ पाए हैं कि यहां हम आपसे किस एक्टर के बात कर रहे हैं ? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए. हम आपको बता देते हैं कि यहां बात हो रही है विकी कौशल की. जिन्होंने संघर्षों से लड़ते हुए बॉलीवुड में कभी छोटे-मोटे रोल भी किए और आज उनकी गिनती सबसे बेहतरीन एक्टर्स में होती है. इन दिनों वो 800 करोड़ी फिल्म 'छावा' से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं.

पहली सैलरी थी 1500 रुपये

विकी का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता शाम कौशल ने भी इंडस्ट्री में काम किया और वो एक्शन डायरेक्टर हैं. हालांकि पिता के बॉलीवुड में होते हुए भी विकी ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी अलग और खास पहचान बनाई. कभी अपनी फैमिली के साथ 10म10 के कमरे में रहने वाले विकी बॉलीवुड में आने से पहले थिएटर में काम करते थे. उन्होंने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वो थिएटर में प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते थे, तब उन्हें पहली सैलरी 1500 रुपये मिली थी.

800 करोड़ी 'छावा' से हिला दिया बॉक्स ऑफिस

विकी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में आई फिल्म 'मसान' से किया था. इसमें उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया. इसके बाद वो संजय दत्त के जीवन पर बनी फिल्म 'संजू' में संजय के दोस्त के किरदार में नजर आए थे. हालांकि उन्हें पहली बड़ी और खास पहचान 2019 में आई फिल्म 'उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक' से मिली. इसके बाद उन्होंने 'सैम बहादुर', 'सरदार उधम' और 'राजी' जैसी फिमों से भी सुर्खियां बटोरी. लेकिन उनके करियर में संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म 'छावा' मील का पत्थर साबित हुई. इसी साल फरवरी में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं और अब भी छावा सिनेमाघरों में टिकी हुई है.

सनी-बॉबी देओल को एक्टर नहीं बनाना चाहते थे पिता धर्मेंद्र, बेटों की इन चीज़ों पर लगा रखी थी पाबंदी

देओल परिवार इस वक्त पूरी इंडस्ट्री में छाया हुआ है. सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया हुआ है. गदर 2 के जरिए सनी देओल और एनिमल के जरिए बॉबी को उनका खोया हुआ स्टारडम हासिल हो चुका है. अब देओल ब्रदर्स बॉलीवुड से लेकर साउथ तक चर्चा में हैं. हाल ही में सनी पाजी की ढ्ढ्ढ भी रिलीज हुई है. हालांकि उनकी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उनके पास में कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं. इसी बीच बॉबी देओल ने बताया कि उनके पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र उन्हें हीरो नहीं बनाना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनके बेटे कुछ और काम करें.इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू के दौरान बॉबी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर बात की. बॉबी देओल ने बचपन से जुड़ा किस्सा सुनाया और बताया कि उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में आएं. वो हमेश उन्हें इससे दूर रखना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करें और किसी दूसरी फील्ड में अपना करियर सेट करें. इसके पीछे की वजह भी बॉबी ने बताई. उनके पिता का मानना था कि इंडस्ट्री में काफी उतार-चढ़ाव हैं और वो अपने बेटों को इन सब से दूर रखना चाहते थे, ताकि वो लोग इससे न गुजरें.

बेटों पर लगा रखी थी धर्मेंद्र ने पाबंदी

इसके अलावा बॉबी देओल ने ये भी कहा कि पिता धर्मेंद्र ने उन्हें इसलिए भी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखा ताकि वे इसके नकलीपन से बच सकें. उन्होंने याद किया कि उन्हें स्टार किड्स की बर्थडे पार्टियों में जाने की मनाही थी और वे एक साधारण घर में पले-बढ़े थे, जहां कभी फिल्मों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था. एक्टर की मानें तो जब भी वो फिल्मों के सेट पर या घर पर अपने पापा के फैन्स को देखते थे, उनसे मिलने वाले प्यार को देखते थे, तो वो हैरान रह जाते थे.

इन प्रोजेक्ट्स में दिखेंगे बॉबी देओल

बॉबी देओल की अपकमिंग प्रोजेक्टस की बात करें तो वो ढ्ढ्ढ की फिल्म अल्फा में नजर आएंगे. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड में नजर आएंगी. वहीं उनके पास आश्रम 4 भी है. एनिमल के बाद अभी तक बॉबी देओल हिंदी फिल्म ने नजर नहीं आए हैं. हालांकि साउथ में उनकी दो फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. बॉबी देओल ने अपने काम से एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया है.

572 करोड़ी फिल्म देते ही

रणवीर-दीपिका

ने रचा लिया था ब्याह, शादी में उड़ाए थे इतने करोड़

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड का स्टार कपल कहा जाता है. दोनों ने ही हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है. रणवीर और दीपिका दोनों ही बॉलीवुड में करीब डेढ़ दशक से काम कर रहे हैं और सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं. रणवीर और दीपिका ने बड़े पर्दे पर साथ में भी स्क्रीन शेयर किया है.साथ काम करने के दौरान रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए थे. बताया जाता है कि दोनों की नजदीकियां 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के दौरान बढ़ी थीं. फिल्म के सेट पर दोनों को प्यार हो गया था. एक तरफ ये फिल्म बड़े पर्दे पर छा गई और दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे. सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर अपनी एक 572 करोड़ी फिल्म के बाद धूमधाम से शादी कर ली थी. आइए जानते हैं कि वो फिल्म कौन सी थी और रणवीर-दीपिका ने अपनी शादी में कितने करोड़ खर्च किया था ?

'पद्मावत' ने कमाए थे 572 करोड़

'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण फिल्म 'पद्मावत' में नजर आए थे. हालांकि इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे. जहां रणवीर ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया था तो वहीं दीपिका रानी पद्मावती में किरदार में दिखाई दी थीं. फिल्म का हिस्सा शाहिद कपूर भी थे. 25 जनवरी 2018 को रिलीज हुई इस पिक्चर का बॉक्स ऑफिस पर सैलाब आया था. संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी पद्मावत का बजट 88 करोड़ रुपये था, जबकि इसने दुनियाभर में 572 करोड़ रुपये कमाते हुए ब्लॉकबस्टर का दर्जा पाया.

शादी में आया था 95 करोड़ का खर्च

साल 2018 में ही पद्मावत की अपार सफलता के बाद रणवीर और दीपिका ने अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया था. नवंबर 2018 में दोनों ने इटली के लेक कोमो में धूमधाम से शादी रचाई थी.

साइबर और स्पेस डोमेन तेजी से नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभरे

टेक्नोलॉजी के तेजी से हो रहे विकास के कारण भविष्य के युद्धों की तस्वीरें भी काफी हद तक बदल गई

नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भविष्य के सैन्य युद्धों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज साइबर और स्पेस डोमेन तेजी से नए युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया में नैरेटिव और परसेप्शन का भी एक युद्ध चल रहा है। इसलिए हम भारतीय सेनाओं को इन मल्टी स्पेक्ट्रम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संघर्ष और युद्ध ज्यादा हिंसक और अप्रत्याशित होंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी के तेजी से हो रहे विकास के कारण भविष्य के युद्धों की तस्वीरें भी काफी हद तक बदल गई हैं। राजनाथ सिंह राजधानी में 'द वीक डिफेंस कॉन्क्लेव' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय रक्षा मजबूत हुई है, क्योंकि हमने उसे भारत की रक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार मजबूत किया है। इसका मतलब है कि आज न केवल भारतीय रक्षा क्षेत्र मजबूत है, बल्कि भारत का ढांचा भी मजबूती के साथ पूरी दुनिया में उभर रहा है। वह दिन दूर नहीं, जब भारत सिर्फ एक विकसित देश के रूप में सामने नहीं आएगा, बल्कि हमारी सैन्य शक्ति भी दुनिया में नंबर वन बनकर उभरेगी। डिफेन्स सेक्टर में आत्मनिर्भरता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए और अपने सुरक्षा उपकरणों को और भी मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। यह संकल्प सिर्फ एक टैग लाइन नहीं है, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के इस डिफेंस कॉन्क्लेव की थीम फोर्स फॉर दि फ्यूचर है। इसलिए सरकार में आने पर हमारे सामने डिफेंस को लेकर एक अजीब सोच को लेकर सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय फोर्स फॉर दि फ्यूचर की बात सोचने का भी साहस लोग नहीं करते थे क्योंकि कोई भी मौजूदा तैयारी दिखाई नहीं देती थी। देश में एक मजबूत डिफेंस सेक्टर होना चाहिए, इस पर कोई काम मजबूती से नहीं हो रहा था। अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उस समय की सरकार की बस यही सोच थी, बहुत होगा तो आयात कर लेंगे। सबसे पहले हमने फैसला लिया कि भारत अपनी डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और देश में एक ऐसा रक्षा औद्योगिक परिसर तैयार करेगा, जो केवल भारत की जरूरतों को नहीं, बल्कि दुनिया में रक्षा निर्यात को भी मजबूत करेगा।

राहुल गांधी लोको पायलटों की अमानवीय कार्य स्थितियों को लेकर सरकार पर हमलावर

नई दिल्ली

कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोको पायलटों की कार्य स्थितियों को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आज यहां कहा कि अमानवीय परिस्थितियों में काम करना न केवल लोको पायलटों के साथ अन्याय है बल्कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक रिपोर्ट को साझा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि रेलवे ने कई परिस्थितियों में छुट्टी की मांग को खारिज कर दिया और महिला कर्मचारियों के हवाले से कहा गया कि उन्हें शौचालय की सुविधा के बिना आठ घंटे की ड्यूटी करनी पड़ी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले साल जब मैं रेलवे के लोको पायलटों से मिला तो उनकी स्थिति जानकर गहरी चिंता हुई थी – 14-14 घंटे की शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी, न पर्याप्त आराम, न खाने का ब्रेक और न शौचालय की सुविधा। हादसों के बाद रेलवे मानवीय चूक कहकर पल्ला झाड़ लेता है लेकिन यह नहीं बताता कि कर्मचारियों से कैसे अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि लोको पायलटों की बुनियादी मांगें थीं – काम के घंटे तय हों और बेहतर माहौल मिले। सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए कमेटी बना दी, समाधान की कोई मंशा नहीं थी। अब खाना और टॉयलेट ब्रेक जैसी मांगें भी यह कहकर ठुकरा दी गई हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये न सिर्फ लोको पायलटों के साथ अन्याय है, बल्कि उन करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है जो ट्रेनों से सफर करते हैं। यह न्याय की लड़ाई है और हम इसमें लोको पायलटों के साथ हैं – जब तक सरकार बहरी बनी रहेगी, आवाज उठाते रहेंगे।

भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए: भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश के कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से जो कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब उन्हें देना पड़ रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि एक ऐसा भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार इस देश में है, जो हर कानून को तोड़ता है। क्योंकि उनको जनता की चिंता नहीं, बल्कि अपने दामाद की चिंता है। एक ईमानदार सरकार की ताकत क्या होती है, ये भारत में अब जनता को पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, किसानों से हड़पी गई जमीन को वापस लेकर किसानों को देंगे। जनता की गाढ़ी कमाई अगर नकली गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी में डाली है, उसकी एक-एक पाई वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि नकली गांधी परिवार खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर है। क्योंकि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बनकर किसानों की जमीन हड़पते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है, सोनिया गांधी का नाम चॉपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है।\पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी आज दंगो और गुंडों का पर्याय बन चुकी हैं। उन्होंने संविधान की रक्षा और संविधान का पालन करने की शपथ ली थी। जब एक कानून संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश का कानून बन गया, तो एक मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करूंगी। ये संविधान का उल्लंघन है।

भारत उपयुक्त नीतियों और दीर्घकालिक निवेश के साथ वैश्विक व्यवधानों से निपट लेगा: निर्मला

नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि संरक्षणवादी नीतियों के बढ़ने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका है, लेकिन भारत उपयुक्त नीतियों और दीर्घकालिक निवेश के साथ वैश्विक व्यवधानों से निपट लेगा। वैश्विक व्यापार युद्ध को लेकर जारी चिंताओं बीच सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान मजबूत घरेलू आधार बनाने पर रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियमों पर आश्वासन दिया कि भारत अपनी नीतियों के साथ इन 'वैश्विक व्यवधानों' से निपट लेगा। उन्होंने कहा कि भारत इन वैश्विक व्यवधानों से बाहर निकलने के लिए काम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है। उन्होंने बाजारों में खुदरा निवेशकों के भरोसे की सराहना भी की।

यमुना नदी की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को यमुना नदी की मौजूदा स्थिति का आकलन, इसकी सफाई और कायाकल्प के लिए चल रही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नदी को साफ करने के लिए एजेंसी-वार कार्य योजना की समीक्षा की गई। कार्य योजना में अल्पकालिक गतिविधियां (3 महीने), मध्यम अवधि की गतिविधियां (3 महीने से 1.5 वर्ष) और दीर्घकालिक गतिविधियां (1.5 से 3 वर्ष) शामिल थीं। नाली प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, सेप्टेज और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान और निगरानी उपायों, यमुना नदी में प्रवाह में सुधार, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा, हरित नदी तट विकास और सार्वजनिक आउटरीच के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों पर विशिष्ट समयसीमा के साथ चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था।

शिवराज चौहान ने ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन प्लांट और टमाटर के खेतों का किया दौरा

नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक के लिए इन दिनों ब्राजील प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन प्लांट और टमाटर के खेतों तथा कुछ अन्य संस्थानों का दौरा किया। शिवराज सिंह ने वहां खेती में अपनाई जा रही मैकेनाइजेशन और सिंचाई की अत्याधुनिक पद्धतियों का अवलोकन करने के साथ ही इसे किसानों के दृष्टिकोण से समझा ताकि भारतीय किसानों को नई पद्धतियों का लाभ पहुंचाया जा सके। ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन संयंत्र का अवलोकन करते हुए शिवराज सिंह ने भारत में सोयाबीन के क्षेत्र के विकास की चिंता करते हुए कहा कि देश में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़े और इसके प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम ब्राजील के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। अभी ब्राजील से भारत सोया तेल आयात करता है लेकिन चर्चा के दौरान यह बात आई कि वह निवेश करे और सोया के प्रोसेसिंग प्लांट लगें तथा सोया का तेल भारत से भी निर्यात किया जा सके। शिवराज सिंह ने बताया कि मैंने जो प्रेजेंटेशन देखा, उसमें कपास को चुनना भी है तो सीधे हार्वेस्टर से निकालते हैं। जो रिसर्च और शोध ब्राजील में चल रहे हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर करें ताकि हम और अच्छे बीज बना सकें। उन्होंने बताया कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाने समेत विभिन्न बिषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि के और तेजी से विकास के लिए मैंने आमंत्रित किया है कि ब्राजील से भी प्रतिनिधिमंडल आए और सारी संभावनाओं को तलाशे। भारत से भी पूरा सहयोग मिलेगा और पूरा विश्वास है कि दोनों देश, यहां की बिजनेस कम्युनिटी भी प्रभावी ढंग से फिर भारत के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी इत्यादि बढ़ाने पर गंभीरता से न केवल विचार करेगी, बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगी।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन की पूछताछ

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित जमीन से जुड़े सौदा मामले में लगातार तीसरे दिन लगभग 6.30 घंटे तक पूछताछ की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा से इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 6-6 घंटे की पूछताछ की थी। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कल पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से रवाना हो गए।

ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जितने दिन भी बुलाएं, हम उपस्थित होंगे। वाड्रा ने कहा कि सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इनके जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। गुरुग्राम में स्थित जमीन सौदा से जुड़ा ये मामला साल 2008 का है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे।

इसी दौरान रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी। इस जमीन का म्यूटेशन कुछ घंटों में ही पूरा करवा लिया गया।

पीएम मोदी से लेकर मीडिया तक को नियंत्रित कर लड़ेंगे बिहार चुनाव: कांग्रेस

पटना

राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में संपन्न हो गई। गुरुवार दोपहर तीन घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीट बंटवारे की बात पर तो किसी नेता ने कुछ नहीं कहा लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। यह बात स्पष्ट हो गई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में चुनाव को सीट बंटवारे, कैंपेन से लेकर घोषणापत्र तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी ही चुनाव से जुड़ा सारा काम देखेगी। इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे।

हड्ह प्रीमियर लीग संस्करण-7 हड्ह स्पोर्ट्स, विनर स्पोर्ट्स, गामा और गीवा मोबाइल और HP मोटर्स द्वारा संचालित

दिव्या दिल्ली : विजेता स्पोर्ट्स हब द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में डेंजर इलेवन और स्पार्टन इलेवन आमने-सामने हुई। डेंजर इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 137 रन बनाए। सुमित (25 रन), पुनित कालरा (26 रन) और सौरभ ढींगरा (25 रन) ने टीम को मजबूत शुरूआत दी। जवाब में, स्पार्टन क ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को महज 16.4 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। राहुल ने 39 रन, कुणाल ने 20 रन और ऑलराउंडर रोहन ने 28 रन के साथ-साथ 4 विकेट झटके। उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उन्हें "प्लेयर ऑफ द मैच" चुना गया, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) लेवल-1 कोच और विजेता स्पोर्ट्स हब के मालिक राहुल वर्मा द्वारा प्रदान किया गया। वहीं, डेंजर इलेवन की ओर से दमदार लड़ाई दिखाने वाले पुनित कालरा को "फाइटर ऑफ द मैच" से सम्मानित किया गया। मुकाबला रोमांचक रहा और दर्शकों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिला। टूर्नामेंट के आगे के मुकाबलों के लिए सभी टीमें कमर कस चुकी हैं!

दिल्ली के कई इलाकों में 21 अप्रैल को जल की आपूर्ति बाधित रहेगी

नई दिल्ली

दिल्ली के कई इलाकों में 21 अप्रैल को दिल्ली जल बोर्ड की जल आपूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने गुरुवार को एक नोट जारी करके यह जानकारी दी है।

दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 21 अप्रैल को दिल्ली के कुछ इलाकों में दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक और द्वारका के इलाकों में सुबह दस बजे से रात दस बजे तक जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक कान्हेला मोड़ पर 1200 मिमी व्यास की मुख्य पानी की पाइपलाइन में इंटरकनेक्शन कार्य की वजह से 21 अप्रैल को दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक जल की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसका प्रभाव

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397